The House reassembled after lunch at six minutes past two of the clock,
MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair.*

SHRI JAIRAM RAMESH (Karnataka): Sir, I have a point of order. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What is the point of order? ...(*Interruptions*)... Why do you want to create problem for me?

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, this is the second day in a row that the House is beginning at five minutes past two. Although we have been sitting here, waiting for the House to begin at two, the Minister of Parliamentary Affairs is also not here. The job of ensuring quorum is that of the Government. Sir, this cannot be allowed to continue like this. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There was no quorum. ...(*Interruptions*)... That is the reason. ...(*Interruptions*)...

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, you have to insist that we begin at two. ...(*Interruptions*).. We have to begin at 2 o'clock. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It was lack of quorum. ...(*Interruptions*)...

SHRI JAIRAM RAMESH: Then, please do not adjourn till 2 o'clock. ...(*Interruptions*).. Please say, 'adjourned till you have the quorum'. ...(*Interruptions*)... Please say that.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Jairam Ramesh, it was delayed by five minutes because of lack of quorum. But, your point is well taken. I would request the Members to ensure that they are present at 2 p.m. itself so that the House commences on time. ...(*Interruptions*)... No, there are other Ministers. ...(*Interruptions*)... I need not insist for a particular Minister. I want Ministers. That's all. ...(*Interruptions*)...

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION (SHRI ASHOK GAJAPATHI RAJU PUSAPATI): Sir, Ministers are always present. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. ...(*Interruptions*)... Now, Shri Ramkumar Verma. Kindly adhere to time. Ramkumar Vermaji, your time is ten minutes. You can start and speak for ten minutes.

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS — *Contd.**

श्री रामकुमार वर्मा (राजस्थान): ऑनरेबल डिप्टी-चेयरमैन सर, मैं सब से पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया।

---

* Further discussion on the Motion moved by Shri Ravi Shankar Prasad on the 2nd February, 2017 and the amendments moved thereto, continued.

[श्री रामकुमार वर्मा]

सर, यह मेरे लिए महत्वपूर्ण अवसर है क्योंकि मैं पहली बार बोल रहा हूं। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि मेरी स्पीच को maiden speech माना जाए। सर, माननीय राष्ट्रपति जी के संयुक्त सत्र में दिए गए अभिभाषण को एक ऐतिहासिक संयुक्त सत्र के रूप में माना गया। यह ऐतिहासिक इस रूप में माना गया कि पहले आम बजट जो फरवरी के अंत में होता था, उसे उससे पूर्व 1 फरवरी को प्रस्तुत किया गया और साथ में रेल बजट प्रस्तुत किया गया। भारत सरकार और उसके नेतृत्व के निर्णय से निश्चित ही राष्ट्रपति जी का अभिभाषण एक तरह से प्रशंसनीय अभिभाषण रहा। उससे मंत्रालयों को बजट राशि का समय पर आवंटन होगा, दूसरे रेल बजट जो पहले अलग से होता था, उसका आम बजट में विलय होने से निश्चित है कि उससे बहुत सारा समय बच गया। महोदय, मैं समझता हूं कि इससे भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा जो जन-कल्याणकारी योजनाएं लागू की जाती हैं, उनको समय पर राशि का आवंटन मिलेगा और उसमें एक गति आएगी और उनमें कोई रुकावट नहीं होगी।

माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जनशक्ति को नमन किया गया है। महोदय, इस सदन में मेरा यह पहला अवसर है। पूर्व के राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में या इस तरह के किसी भी अवसर पर नमन किया गया या नहीं किया गया मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस अभिभाषण में नमन किया है। भारत की जनता की वह शक्ति है, जिसके अंदर इतनी ताकत है और इतनी समझदारी और परिपक्वता है कि उसको नमन करना अतिशयोक्ति नहीं है। माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में इस जनशक्ति को नमन करने का काम किया है। यह नमन किसी एक पंक्ति के द्वारा नहीं किया है। मैं इसके लिए यह कहना चाहूंगा कि भारत की जनता साक्षरता में कम हो सकती है। यह जनता गरीब है, मजदूर है, किसान है, दलित और शोषित है। इसके साथ ही साथ इसमें एक महिला वर्ग भी इतना है कि वह साक्षरता में पुरुषों की तुलना में कम है, लेकिन इस भोली-भाली जनता के अंदर इतनी समझ है, इतनी परिपक्वता है कि उसकी ताकत से देश का नेतृत्व करने वाला कोई व्यक्ति यदि देश हित में और जनता के हित में कार्य करता है, तो इस देश की जनता उसको अपना समर्थन और शक्ति देती है, जिसको नमन करना हमारा परम कर्तव्य बनता है।

मैं इसके लिए दो उदाहरण देना चाहूंगा। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि समय की सीमा है। महात्मा गांधी जी देश के राष्ट्रपिता कहलाए, Father of the Nation. जब महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन चलाया, तो उस समय देश के अंदर ब्रिटिश हुकूमत थी, जिसने 200 वर्षों तक शासन किया और उससे पहले भी देश गुलाम हुआ था। उस समय अंग्रेज़ी शासन की जड़ें बहुत मजबूत थीं और उन्होंने सोचा था कि इस देश से ये जड़ें नहीं निकलेंगी। यह देश हमारे अधीन रहेगा और हम इस देश पर राज करते रहेंगे, लेकिन महात्मा गांधी जी ने देश की स्वतंत्रता के आंदोलन का नेतृत्व किया। इस कार्य में देश की जनता ने उनका साथ दिया। मैं नहीं कहता कि महात्मा गांधी इस कार्य में केवल अकेले व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने देश की जनता के भाव, उसके विचार और संस्कृति को देश की धरोहर समझा। उन्होंने यह भी समझा कि इस देश की जनता के दिल और दिमाग में राष्ट्रीयता की एकता है और राष्ट्र के लिए समर्पित है, महात्मा गांधी जी ने इसको पहचाना। इसमें उद्धरण भी दिया है, चम्पारण के सत्याग्रह का शताब्दी वर्ष। चम्पारण के सत्याग्रह का वह समय निश्चित ही नहीं भूला जाएगा। गांधी जी ने इस बात को महसूस किया कि मेरे देश की जनता गरीब है। उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं और खाने के लिए रोटी

नहीं है। इस ब्रिटिश हुकूमत में रहते हुए निश्चित है कि देश के करोड़ों गरीब लोग जो शोषित हैं, इनको आजादी की जरूरत है। वे जनता के साथ में मिलकर चले और पूरे देश में उन्होंने भ्रमण किया। देश की जनता को उनके नेतृत्व में विश्वास जगा और सबने मिलकर इस देश को आजादी दिलाई। यह जनशक्ति का एक परिचय था। यदि मैं इसी रूप में कहूं कि Father of the Nation, तो वे न केवल भारत में बल्कि विश्व में एक अद्भुत व्यक्तित्व के रूप में उभरे। उन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश से ऐसी हुकूमत को दूर किया।

मैं इस अवसर पर भारत रत्न डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी का नाम लेना चाहूंगा कि उनको भी इस जनशक्ति ने समझा और अम्बेडकर जी ने इस जनता के दर्द को समझा। उन्होंने विभिन्न परिस्थिति में जिस प्रकार से अध्ययन किया और यहां की परिस्थितियों को समझा कि भारत में विभिन्नता है, बहुत सारी विषमताएं हैं और गरीबों के साथ क्या होता है। जब उन्होंने करोड़ों लोगों की पीड़ा को समझा, तो उसी का रिजल्ट निकला कि इस देश की जनशक्ति के जो करोड़ों लोग गरीब थे, जो दलित थे, उनके साथ मिलकर उन्होंने एक प्रण और संकल्प लिया। इसी कारण उन्होंने भारत को एक अनूठा संविधान दिया। आज डॉ. अम्बेडकर जी को भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में भारत के संविधान निर्माता के रूप में देखा जाता है।

सर, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आज माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जो जनशक्ति के नमन की बात है, यह नमन भारत सरकार और भारत सरकार के नेतृत्व के द्वारा किया गया है। उसका कारण यह है कि भारत सरकार के नेतृत्व में जिस दिन उन्होंने इस देश की बागडोर संभाली, तब उन्होंने यह प्रण किया था कि मैं भारत के एक प्रधान सेवक के रूप में कार्य करूंगा, न कि एक प्रधान मंत्री के रूप में। दिल और दिमाग में पीड़ा थी, दर्द था कि इस देश की जनता में वह ताकत है, जिसने मुझे यहां पर भेजा है। उनके ये महापुरुष उदाहरण भी थे — वे महात्मा गांधी जी का उदाहरण दें, डॉ. अम्बेडकरजी का दें, औरों का दें। उन्हें यह भी मालूम था कि अगर व्यक्ति कोई कार्य करता है तो इस देश की अनेकता में एकता का एक बहुत प्रखर भाव इस देश के लोगों के अंदर है। भारत सरकार के नेतृत्व में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश को नमन करते हुए, इस संसद को नमन करते हुए, निर्धन को, गरीब को, किसान को, मजदूर को और वंचितों को नमन करते हुए कहा था कि मैं आपका सेवक हूं और उस तरह के कार्य करूंगा जिससे कि देश के करोड़ों-करोड़ दलित वर्ग के लोग, जिनके मैंने वर्षों से बहुत-से नारे, स्लोगन्स सुने हैं, लेकिन उनके कार्य नहीं हुए हैं, मैं उनके कार्य पूरे करूंगा।

आदरणीय उपसभापति जी, मैं इस संबंध में कहना चाहूंगा कि "जन-धन योजना", एक ऐसी योजना है, जिससे इस देश के आम आदमी को, गरीब आदमी को जोड़ा गया। जोड़ने का यह निर्णय इसलिए लिया गया ताकि भारत के banking system से जो किसान हैं, मजदूर हैं, जो कम पढ़े-लिखे व्यक्ति हैं, वे सब इससे जुड़ें। भारत की सत्तर साल की आजादी में, या यूँ कहें कि banking nationalization से लेकर बाद में, अभी भी, पिछले वर्षों में, भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा बार-बार यह प्रयास किया गया कि लोग देश के अंदर banking system को जानें, पहचानें। उन्होंने इस तरह की पहल की है और इसके लिए वे जनता के द्वार भी गए। इसके और भी प्रोग्राम किए गए।

इसमें फायनेंशियल लिटरेसी और इंक्लूज़न की बात कही गई, लेकिन यह इतना सफल नहीं हुआ। भारत की सरकार के नेतृत्व में इसका आह्वान किया गया। लोग वर्षों से banking system

[श्री रामकुमार वर्मा]
से नहीं जुड़ रहे थे, लेकिन "जन-धन योजना" से यह संपन्न हुआ। इस योजना के आह्वान के साथ यह कार्य किया गया। यह एक गर्व की बात है कि 26 करोड़ से अधिक लोगों ने खाते खुलवाए। इतना ही नहीं 13 करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा की जो कल्याणकारी योजनाएँ थीं, उनसे जोड़ा गया और 47,000 करोड़ रुपये का अमाउंट खातों के अंदर आया। यह एक छोटी-सी बात नहीं थी। जब "जन-धन योजना" की बात आई, तो यह एक कल्पना के रूप में है, लोगों ने इस तरह का rumour भी फैलाया था।

डिप्टी चेयरमैन सर, इस देश में जो गरीब है, उसके लिए यह है ...(**समय की घंटी**)... जन-धन के अकाउंट खोले जाएंगे। सर, क्या आपने मुझे दस मिनट दिए हैं?

एक माननीय सदस्यः इनकी मेडन स्पीच है।

श्री उपसभापतिः मेडन स्पीच है?

श्री रामकुमार वर्माः अच्छा, दस मिनट हो गए हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Take two more minutes.

SHRI RAMKUMAR VERMA: Sir, it is my maiden speech.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is not your maiden speech.

श्री रामकुमार वर्माः मैं कहना चाहूंगा कि जो योजनाएँ बनीं, जो कल्याणकारी योजनाएँ ..(**व्यवधान**)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Vermaji, you made your maiden speech on 2.8.16.

श्री रामकुमार वर्माः सर, 2.8.16 को तो मैंने हल्का सा, पांच एक मिनट का बोला था। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः मैं क्या करूँ? What can I do? So, you take two more minutes. Okay.

श्री रामकुमार वर्माः फाइव मिनट्स और दीजिए। उपसभापति जी, मैं यह निवेदन करना चाह रहा था कि आज "जन-धन योजना" और "उज्ज्वला योजना" के द्वारा जो इस तरह का कार्यक्रम हुआ है, उसने यह सिद्ध किया है कि भारत की जनता में दान करने की कितनी क्षमता है और देश को सुधारने की कितनी प्रवृत्ति है। भारत की जनता ने यह कार्य किया है। सब्सिडी के बारे में मैं समझता हूं कि गरीब, सपने में भी यह नहीं सोचता था कि उसको मिलेगी। सर, मैं भी इसका भुक्तभोगी हूं। 1985 में जब मेरे घर पर चूल्हा जलता था, तो मैं सोचता था कि मुझे गैस कैसे मिलेगी? उस समय यह देखा जाता था कि यदि 20 हजार रुपये होंगे, तो गैस मिलेगी। मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी होती है और मैं इसके लिए माननीय राष्ट्रपति महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूं कि देश में 0.2 करोड़ लोगों ने सब्सिडी छोड़ी और 1.5 करोड़ ऐसे लोग, जो सपने में भी नहीं सोचते थे कि हमारे लिए कभी धुआँरहित गैस का चूल्हा होगा, उनको सुविधा मिली। इस तरह "स्वच्छ भारत अभियान" की बुनियाद के लिए लोगों ने जन आंदोलन किया। उन्होंने स्वच्छता की बात करके सोचा था कि कहां स्वच्छ भारत करने चले? लेकिन यह देखकर अच्छा लगता है

कि आज 1,40,000 गांवों में, 4.5 से ज्यादा शहरों में, 77 ज़िलों में और 7 राज्यों ने अपने क्षेत्र को खुले में शौच से मुक्त कर दिया है। यह घोषित भी किया गया है। आदरणीय उपसभापति जी, इसी के साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि 8 नवंबर, 2016 को जिस तरह से डिमॉनिटाइजेशन किया गया, यह डिमॉनिटाइजेशन भारत के उन करोड़ों-करोड़ गरीबों के लिए था, उन शोषित वर्ग के लिए था, किसानों के लिए था, मजदूर वर्ग के लिए था। दो नंबर का काला धंधा करने वालों ने देश में इस तरह का माहौल पैदा कर दिया था कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका था और गरीब व्यक्ति, जो मेहनतकश व्यक्ति था, उसको न्याय नहीं मिल रहा था। वे उसकी मेहनत की कमाई को, दो नंबर का काला धन करते थे। उससे निश्चित ही यह हुआ कि काले धन पर रोक लगी, भ्रष्टाचार पर रोक लगी, जाली नोटों पर रोक लगी। आतंकवाद को और हवाला मार्किट को ...(**समय की घंटी**)... बहुत बड़ी बुराई का अंत हुआ। ..(**व्यवधान**)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, please conclude.

श्री रामकुमार वर्माः इस तरह से भारत सरकार के द्वारा, उनके नेतृत्व में ये अभूतपूर्व निर्णय हुए। डिप्टी चेयरमैन सर, मैं कहता हूं कि हम दलित समाज की बातें बहुत करते हैं, लिखित पीड़ा भी करते हैं, लेकिन दलित समाज के लिए बाबा साहेब अम्बेडकरजी ने कहा था रिज़र्वेशन हो ताकि यह वर्ग आर्थिक क्षेत्र में मजबूत हो। इसके लिए रिज़र्वेशन की पहल अवश्य की गई, लेकिन 70 साल तक भी implementation नहीं हुआ। आज भारत सरकार के नेतृत्व में यह किया गया। जब व्यक्ति का आर्थिक विकास होगा, तभी उसका शैक्षणिक विकास होगा। उसके आर्थिक विकास के लिए ही इस तरह की जनकल्याणकारी विभिन्न योजनाएँ बनीं। मैं कहता हूं कि 84 योजनाओं में से 50 परसेंट से ज्यादा योजनाएँ, चाहे वह Stand-up योजना हो, मुद्रा बैंकिंग योजना हो, Start-up योजना हो, लाभकारी योजनाएँ हैं। जो "दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना" है, यह प्रधान मंत्री जी की किसानों के लिए योजना है। आज उनको इस योजना से काफी राहत और आशा मिली है कि इस देश के अंदर ऐसा नेतृत्व आया है जो गरीबों का मसीहा होगा। ...(**समय की घंटी**)... गरीबों की सुनेगा। मैं आपको इस पर धन्यवाद देते हुए माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद व्यक्त करता हूं। जय भारत।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I know that Shrimati Viplove Thakur is to speak next. She is a very generous hon. Member. Shri Prem Chand Gupta had requested that since he has to go early on an urgent matter, I am allowing him with your permission.

SHRIMATI VIPLOVE THAKUR (Himachal Pradesh): Okay, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: She is very generous.

श्री प्रेम चन्द गुप्ता (झारखंड)ः ये बड़ी बहिन हैं।

माननीय उपसभापति महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का आपने मुझे मौका दिया है और वह भी आउट ऑफ टर्न दिया है, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। उपसभापति जी, राष्ट्रपति जी हमारे माननीय हैं, हमारे देश के संविधान के सर्वमान्य संरक्षक हैं, हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन उनके द्वारा दिए गए अभिभाषण में सरकार की जिन नीतियों को हाइलाइट किया गया है, हम उससे सहमत नहीं हैं।

[श्री प्रेम चन्द गुप्ता]

श्रीमान् जी, देश का जो किसान है, जो देश का अन्नदाता है, जो अपनी मेहनत और पसीने से, मेहनत करके, देश के सवा सौ करोड़ लोगों का पेट भरता है, देश के लोगों के लिए अनाज पैदा करता है, आज उसकी बड़ी दुर्दशा है, उसकी हालत बहुत खराब है, चिंताजनक है।

श्रीमान् जी, उसको खाद नहीं मिलती, बीज नहीं मिलता और नोटबंदी ने तो उसकी और भी बरबादी कर दी। आज ये हालात हैं, आप सभी लोगों ने कल भी टी.वी. पर देखा होगा कि टोमेटो सड़ रहा है, पर कोई खरीदार नहीं है। किसान को उसके प्रॉड्यूस का जो पैसा मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा। आप लोगों ने जो वायदा किया था कि किसान की जो लागत होगी, उस लागत पर हम किसान को कम से कम 50 प्रतिशत मुनाफ़ा देंगे, उसका क्या हुआ? सर, हालात ये हैं कि कोल्ड स्टोरेज वालों ने पोटेटो अर्थात् आलू की फसल को बाहर निकालकर फेंक दिया, क्योंकि किसान उनके चार्जज़ पे नहीं कर पाए। आज माननीय राम गोपाल जी नहीं हैं, इलेक्शन में बिजी हैं, हम लोग भी शाम को वहीं जा रहे हैं। श्रीमान् जी, इस एरिया में हजारों टन पोटेटो, आलू सड़ रहा है, क्योंकि 50 पैसे किलो भी यह पोटेटो खरीदने को कोई तैयार नहीं है। मैं साउथ में गया था। ...(**व्यवधान**)... हम यह कोई पोलिटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, जो आप हंस रहे हैं। ग्राउंड, धरातल पर जो समस्या है, उसको आप सुनिए। मैं कोई पार्टी-पोलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। यह समस्या आपकी भी है, हमारी भी है। आप यह बताइए कि अगर किसान को उसकी मजदूरी, उसका पैसा, उसकी मेहनत का पैसा नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? हमारे देश में हर साल दो करोड़ नौजवान तैयार हो रहे हैं, उनमें किसानों के बच्चे भी होते हैं। देश में जो यह नक्सलिज्म और रीजनल डिस्टर्बेंसेज़ होती हैं, यह उन नौजवानों को गुमराह करके उनके थ्रू ही करवाई जाती हैं, जैसे अभी पंजाब में हुआ। वहां काम न होने की वजह से वहां के नौजवानों में नशे की लत डाल दी गई। झारखंड में, छत्तीसगढ़ में नौजवानों को नक्सलाइट बना दिया गया, गलत रास्ते पर डाल दिया गया। यह एक रूट-कॉज़ है। इसमें हंसने की बात नहीं है। देश के सामने यह एक समस्या है। ठीक है, आप बाद में अपना भाषण करिए, आपको भी समय मिलेगा, लेकिन जो एक समस्या है, उसको समझने की आवश्यकता है कि आज किसान जो सुइसाइड कर रहा है, वह क्यों कर रहा है? आपके जो बीजेपी शासित प्रदेश हैं, सबसे ज्यादा तो सुइसाइड उनमें हो रही हैं। महाराष्ट्र में हो रही हैं, छत्तीसगढ़ में हो रही हैं। ये क्यों हो रही हैं, किस लिए हो रही हैं? इस पर सोचने की जरूरत है, न कि इसके ऊपर हंसने की आवश्यकता है।

श्रीमान् जी, जब 2014 में आपकी सरकार बनी, तो सरकार बनने से पहले आपने देश के नौजवानों से, देश के लोगों से वायदा किया था कि हम साठ रोज के अंदर पांच करोड़ रोजगार देंगे और हर साल हम दो करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या आपने अपने इस वायदे को पूरा किया? ठीक है, अगर आपने अपना वायदा पूरा नहीं किया, जो जगजाहिर सत्य भी है, लेकिन आपने इस बारे में क्या स्टेप उठाया? अगर आप कोई रोजगार नहीं दे सके, तो ठीक है कि नहीं दे सके, यह बात समझने की है, लेकिन क्या इस बारे में आपने कोई स्टेप उठाया? आप स्टेप उठाने की बजाय हर दो-तीन महीने में केवल एक नया शगूफा छोड़ देते हैं, कोई न कोई एक नई स्कीम बनाकर छोड़ देते हैं और मेन इश्यू को डायवर्ट करते हैं। श्रीमान् जी, हर साल हमारे देश में दो करोड़ नौजवान नौकरी की तलाश में अपने घर से निकलते हैं। मां-बाप अपनी जमीन-जायदाद बेचकर बच्चों को पढ़ाते हैं और सोचते

हैं कि हमारे बेटे या बेटी को बड़े होकर रोजगार मिलेगा? क्या इस बारे में सरकार ने कोई कदम उठाया है? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कदम आपने उठाया है, जिससे लगे कि आपने इस बारे में ध्यान दिया है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, जैसा मैंने पहले कहा, रोजगार न मिलने से समाज में जो एंटी-सोशल एलिमेंट होता है, वह नौजवान को गुमराह करता है, जैसे मैंने आपके सामने दो प्रदेशों का एग्ज़ाम्पल दिया। देश की आज यह एक बर्निंग प्रॉब्लम है। इस बारे में बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, वरना स्थिति कंट्रोल के बाहर चली जाएगी।

श्रीमान् जी, माननीय प्रधान मत्री जी ने "मेक इन इंडिया" का नारा दिया। हम सब लोग सहमत हैं और हमें खुशी होगी कि देश में सामान बने। हमारे देश में जो आज सामान यूज़ हो रहा है, जो इम्पोर्ट हो रहा है, उससे हमारा देश एक डम्पिंग ग्राउंड बन गया है। श्रीमान् जी, आप यह समझिए कि A to Z, दुनिया भर का जो rejected माल है, वह चीन और दूसरे देशों से हम लोग import करते हैं। हमारी जो small and medium industries हैं, आज वे बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। उसका क्या कारण है? आज आप रोजगार की बात करते हैं। हमारी जो small and medium industries हैं, वे क्यों बंद हुई हैं? ये वे लोग हैं, जिन लोगों ने आप लोगों को बनाया, आपको वोट दिया। आपने तो उनके साथ विश्वासघात किया है, आपने उनको चोर बना दिया, उनके ऊपर इंस्पेक्टर राज थोप दिया। क्या हमारा देश एक dumping ground होकर रह जाएगा या आप इसके बारे में कोई सोच-विचार कर रहे हैं? आज आपके तीन साल हो गए, अब जाने का समय आ गया और आप रोज के रोज कोई न कोई नई स्कीम पब्लिक में लाकर दिमाग को divert करने का काम करते हैं। लेकिन जो चीज आपके सामने है, जो स्थिति, जो समस्या आपके सामने है, आज के रोज जो burning problem है, आप उसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं देते हैं?

श्रीमान् जी, मैं 'ease of doing business' के बारे में बताना चाहूँगा। जब आप सत्ता में आए थे, उस वक्त 'ease of doing business' में हमारे देश की ranking क्या थी और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि हिन्दुस्तान 'ease of doing business' में 142वें स्थान पर चला गया है। आप 'Make in India' बोलते हैं। अगर आपके देश में काम करने का, production करने का, फैक्टरी लगाने का कोई माहौल ही नहीं होगा, तो कहां से आपके यहां investment आएगा और production होगा? मैंने माननीय प्रधान मंत्री जी को कई बार सुना है, मैंने माननीय वित्त मंत्री महोदय को कई बार सुना है, वे 'ease of doing business' की बात करते हैं। निर्मला सीतारमण जी, जो इसकी concerned Minister हैं, मैंने उनको भी सुना है। लेकिन केवल बोलने से 'ease of doing business' नहीं होता है। आपको धरातल के ऊपर माहौल create करना पड़ेगा। आज आपने पूरा इंस्पेक्टर राज कर दिया है। हर चीज इंस्पेक्टर्स के हाथ में है। क्या इसी तरह से कोई इंडस्ट्री लगती है? क्या इसी तरह से job creation होता है? क्या आज सरकार कोई job दे सकती है? सरकार की अपनी limitations हैं।

श्रीमान् जी, आज आप देखते हैं कि सरकार के हर महकमे में vacancy है। दिल्ली यूनिवर्सिटी, दुनिया में जिसका नाम है, आज वहां पर professors की vacancies हैं। Students हैं, students धक्के खाते हैं, उनको admission नहीं मिलता है और आप वहाँ vacancy नहीं भर रहे हैं। यह जो विरोधाभास चल रहा है, इसके ऊपर आप लोग क्या कर रहे हैं? ...(**समय की घंटी**)... इन सबके ऊपर आपने नोटबंदी का जो एक महान step उठाया, श्रीमान् जी, यह एक बहुत बड़ा ill-advised step था। यह step एक ऐसा step था, जिससे आप लोगों ने एक चलती हुई गाड़ी के

[श्री प्रेम चन्द गुप्ता]

टायर को puncture करने का काम किया। दुनिया के बड़े-बड़े Nobel Laureates ने कहा कि इससे बड़ा घातक कोई step नहीं हो सकता। ...(**समय की घंटी**)... श्रीमान् जी, Miscellaneous Group में 19 मिनट बाकी हैं, अभी तो मेरे 9 मिनट हुए हैं, तो kindly allow me some more time.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: One more speaker is there.

SHRI PREM CHAND GUPTA: He is not here, Sir. Please be kind to me.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Then, only one more minute.

श्री प्रेम चन्द गुप्ताः श्रीमान् जी, मैं यह कह रहा था कि यह एक ill-advised step था। देश का हर नागरिक और सारी पार्टियां, हम भी चाहते हैं कि black money के ऊपर control हो, black money को control किया जाए, विदेशों से जो नकली currency आ रही है, उसके ऊपर control किया जाए। हम भी चाहते हैं, कौन नहीं चाहता? देश का कौन सा नागरिक ऐसा है, जो यह नहीं चाहेगा? लेकिन श्रीमान् जी, इस काम के लिए आपने जो ill-advised step लिया, ill-planned step लिया, इससे देश का कितना बड़ा नुकसान हुआ है! श्रीमान् जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विदेशी tourists, जो 6-6 महीने पहले अपनी booking करते हैं, वे आए और उनको daily सिर्फ 600 रुपए change करना allow किया गया। उनको लाइनों में लगना पड़ा। क्या वे लाइनों में लगने के लिए इतना पैसा खर्च करके आए थे?

मान्यवर, स्पेन एक छोटा सा मुल्क है, जिसकी major income और major employment टूरिज्म के ऊपर ही डिपेंड करती है। वहां टूरिज्म उनकी income का सबसे बड़ा स्रोत है। आज हमारे देश में क्या नहीं है? हम अपने देश में टूरिज्म को बढ़ा सकते हैं, लेकिन हो यह रहा है कि टूरिस्ट अपने आप भारत आते हैं, उसमें आज तक किसी भी सरकार का कोई हाथ नहीं रहा है। माफ करना, हमारी सरकार भी रही है और मैं सरकार का हिस्सा भी रहा हूं, लेकिन इस संबंध में किसी ने कुछ नहीं किया। हमारे देश में जो टूरिस्ट आते हैं, वे हमारे monuments, हमारी सभ्यता और संस्कृति को देखने के लिए आते हैं। इसमें किसी भी सरकार का कोई contribution नहीं है। नॉर्मल कोर्स में जो टूरिस्ट यहां पर आ रहे थे, नोटबंदी करके आपने उनके पांव में भी लगाम लगा दी, जिससे उनका पूरा सीज़न ही फेल हो गया। उनको अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ या पत्नी के साथ छुट्टियां बिताने के लिए यहां आना था, लेकिन आप लोगों ने उनके ट्रिप को खराब करने का काम किया। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, please conclude.

श्री प्रेम चन्द गुप्ताः श्रीमान्, मैं regional imbalance की बात कहना चाहता हूं। सत्ता में आने से पहले आपने कहा था कि जो पिछड़े हुए राज्य हैं, हम उनको बढ़ावा देने के लिए कारगर कदम उठाएंगे। बिहार और झारखंड देश के पिछड़े हुए राज्यों में आते हैं, लेकिन केवल झूठे वायदे करने के अलावा आप लोगों ने इन राज्यों के लिए कुछ नहीं किया। आप देखिए, झारखंड से पूरे देश को, minerals जाते हैं, बिहार से पूरे देश को manpower मिलती है। पूरी दुनिया में बिहार के लोगों ने जाकर अपना नाम कमाया है। क्या regional imbalance खत्म करने के लिए

आपने कोई स्टेप उठाया है? मुझे नहीं लगता कि आपने regional imbalance को खत्म करने के लिए आज तक कोई भी स्टेप उठाया हो।

श्रीमान्, आपने hi-tech cities की बात की और कहा कि हम 100 शहर ऐसे बनाएंगे, जो hi-tech होंगे। मैं इस पर आपसे यह कहना चाहता हूं कि आपके पास अभी जो so called millennium cities हैं, जहां IT का इतना बड़ा कारोबार होता, लाखों नौजवान लड़के-लड़कियों को वहां रोज़गार मिला हुआ है, लेकिन आपने आज तक वहां के लिए भी कुछ नहीं किया। आप गुड़गांव चले जाइए, अगर किसी रोज़ बरसात हो जाए, तो सड़क के ऊपर चार-चार फीट पानी भर जाता है और आप 100 hi-tech smart cities बनाने की बात करते हैं। Smart cities तो आप बाद में बनाइएगा, आपके पास अभी जो cities हैं, कम से कम पहले उनको तो बचा लीजिए। ...(**समय की घंटी**)...

श्री उपसभापतिः ठीक है, अब बस कीजिए।

श्री प्रेम चन्द गुप्ताः श्रीमान्, मैं सिर्फ दो मिनट और लूंगा।

आपने रेलवे की बात की है। 2004-2009 के बीच में रेलवे का असली रूप दुनिया के सामने आया कि किसी प्रकार हमारे देश की रेलवे पैसा कमा सकती है, modernization कर सकती है, expansion कर सकती है। उस रेलवे की आज आपके समय में यह स्थिति है कि उसके पास तनख्वाह देने तक के लिए पैसे नहीं हैं, इसके लिए आप market से पैसे borrow करना चाहते हैं। आप bullet train और tube train की बातें करते हैं, जो 1100 से 1200 किलोमीटर की स्पीड से चलेंगी, लेकिन हमारी जो unmanned crossings हैं, जिनके कारण हर रोज़ दस-बीस लोगों की जानें चली जाती हैं और लाखों रुपयों का नुकसान हो जाता है, उनके लिए आप कुछ नहीं कर पाए। रेलवे में सेफ्टी की समस्या है, सर्विसिंग की समस्या है, इसके बारे में आप कुछ नहीं कर रहे हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और मैं चाहता हूं कि इस तरफ आप ध्यान दें।

श्रीमान् जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। आरक्षण के ऊपर आपके आरएसएस के नेतागण और बीजेपी के लीडर्स बार-बार अटैक करते रहे हैं। आप एक बात बिल्कुल क्लीयरली समझ लीजिए कि आरक्षण के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं हो सकता है। हम जानते हैं कि आप लोगों को आरक्षण से समस्या है। श्रीमान्, समाज के जो पिछड़े तबके के लोग हैं, उनको भी तो इस देश में जीने का अधिकार है, particularly जो blue blood या ऊंचे तबके के लोग हैं, यह देश खाली उन्हीं लोगों का नहीं है। जो दलित हैं, पिछड़े हैं, मुस्लिम हैं, उन लोगों ने भी देश की आजादी के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं।

श्रीमान् जी, पहले जब बिहार का चुनाव हुआ था, * ने वहां पर बयान दिया कि हम आरक्षण नहीं दे सकते, आरक्षण को निकालना होगा। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Okay, now conclude... (*Interruptions*)...

श्री ला. गणेशन (मध्य प्रदेश)**:** उपसभापति महोदय, यह अनावश्यक है। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, please conclude.

---

* Expunged as ordered by the Chair.

श्री प्रेम चन्द गुप्ताः श्रीमान् जी, यह तो रिकॉर्ड है। मैं तो ...(**व्यवधान**)... Sir, it is a matter of record. If you want, I can submit a copy of the newspaper.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, please conclude.

श्री प्रेम चन्द गुप्ताः श्रीमान् जी, अभी जयपुर में आपके दूसरे नेताओं ने बोल दिया। आप क्या बोल रहे हैं? यह नहीं हो सकता। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः अब आप कन्क्लूड कीजिए। All right. Now, that is okay; please conclude.

श्री प्रेम चन्द गुप्ताः श्रीमान् जी, मैं इसी के साथ सरकार की नीतियों से अपनी असहमति जाहिर करते हुए, आपका धन्यवाद करता हूं।

श्रीमती विप्लव ठाकुरः माननीय उपसभापति जी, मुझे बोलने के लिए समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं महामहिम द्वारा दिए गए अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। ...(**व्यवधान**)...

SHRI LA. GANESAN: Sir, unnecessarily he is mentioning the name of *. It is irrelevant. Why did he mention the name of *? ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Did you mention any name, Mr. Gupta?

SHRI PREM CHAND GUPTA: Yes, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, then that is expunged.

SHRI LA. GANESAN: Thank you, Sir. ...(*Interruptions*)...

SHRI B. K. HARIPRASAD (Karnataka): Sir, is it unparliamentary?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No; he can't come and defend himself. You can't mention the name and make an allegation against a person who can't come here and defend himself. He made an allegation, or something like that. The name is expunged. ...(*Interruptions*)..

SHRI B. K. HARIPRASAD: He has not made any allegation, Sir.

SHRI JAIRAM RAMESH (Karnataka): There are so many people who can defend him, Sir! ...(*Interruptions*)...

SHRI B. K. HARIPRASAD: He has not made any allegation, Sir. ...(*Interruptions*)...

SHRIMATI VIPLOVE THAKUR: It is a fact. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In any case, Guptaji, you have attributed a quotation to a person who is not present here. ...(*Interruptions*)... It is objected to as an allegation, or as untrue. I expunge it. ...(*Interruptions*)...

---

* Expunged as ordered by the Chair.

You see, there is an objection. An hon. Member says that the allegation is wrong. ...(*Interruptions*)... Mr. Ganesan, do you accept that it is not an allegation? ...(*Interruptions*)... Let him say that. Do you accept that it is not an allegation?

SHRI LA. GANESAN: No, Sir. He has mentioned the name of * and quoted his speech also which is not at all correct. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is the point. ...(*Interruptions*)... Okay, Guptaji, let us not dispute over it. Anyhow, you said something against a person who can't come and defend here; he can't explain it here. So, it is expunged. ...(*Interruptions*)...

SHRI JAIRAM RAMESH: So many statements are attributed to Jawaharlal Nehru, to Indira Gandhi and to all departed leaders. They can't come and defend themselves!

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Don't stretch it like that. If you make a quotation about late Smt. Indira Gandhi or Pandit Jawaharlal Nehru, if anybody objects to that saying that such a statement is not correct, then I will take a decision on that. I have to. ...(*Interruptions*)... Let us not argue over it. Since the quotation of Guptaji has been objected to, I have to take cognizance of that. When one Member has said that that statement is wrong and that there is no such quotation, then I have to take cognizance of that. That is what I have done. That is all I have done. ...(*Interruptions*)... Okay, all right. Are you authenticating that he made a statement like this? ... (*Interruptions*)... Are you saying that he made such a statement and you are authenticating that? ... (*Interruptions*)... Then don't say this. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANAND SHARMA (Himachal Pradesh): Sir, listen to me. ...(*Interruptions*)... Sir, what I am saying is that Shri Prem Chand Gupta has said that he has not made any allegation. Whatever statement was made it has been refuted. ...(*Interruptions*)... What I am saying is both should stay on record. He has said something and he has already refuted it. ...(*Interruptions*)... That is what we are saying. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is applicable if the person is present here. ...(*Interruptions*)... The person is not present here. ...(*Interruptions*)...

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, by that logic, you have to expunge what the Prime Minister says. ...(*Interruptions*)...

SHRI PREM CHAND GUPTA: I stated that it is a matter of record. You yourself know it.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: If it is a record, you could have brought it, read it out and authenticated it. You did not do that. ...(*Interruptions*)...

---

* Expunged as ordered by the Chair.

SHRI PREM CHAND GUPTA: I can do it. ...(*Interruptions*)... I can authenticate. ...(*Interruptions*)... So, don't expunge, Sir. Let it be there. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no, that is expunged. ...(*Interruptions*)... That is expunged.

SHRI PREM CHAND GUPTA: I will authenticate, no problem. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You come, quote from the record and then authenticate. ...(*Interruptions*)... It is a different matter if you come, quote from a record and authenticate it. Now, you attributed a statement to 'x', which was not refuted here. ...(*Interruptions*)... The 'x' is not present. ...(*Interruptions*)... I have to do that. ...(*Interruptions*)... That is over. ...(*Interruptions*)... It is over. ...(*Interruptions*)... Whatever he has said is on record — don't worry — except what I expunged. Now Viploveji.

श्रीमती विप्लव ठाकुरः माननीय उपसभापति जी, मैं महामहिम के अभिभाषण पर बोलने जा रही हूँ। महामहिम का जो अभिभाषण होता है, वह सरकार की पॉलिसीज़ या सरकार की जो नीतियां होती हैं, उनका लेखा-जोखा होता है। उपसभापति जी, यह लेखा-जोखा नहीं है, यह जनता को * है।

इस अभिभाषण में कुछ भी नया नहीं है। मैंने सारा पढ़ा, बहुत बार पढ़ा। इसमें क्या है, वही- 'Sit India', 'Stand India', 'Make India', 'स्वच्छ इंडिया'। यानी इंडिया ही इंडिया है, जनता कहीं पर नहीं है, जनता का नाम ही नहीं है। और क्या कहा गया है— हम यह कर देंगे। अरे भाई, जो आपने 2014 में अपने मेनिफेस्टो और भाषणों में कहा, वह तो आप पूरा कर नहीं सके हैं, तो कहां से नया करेंगे? जो हमारी नीतियां थीं, उनके नाम बदल-बदल के ये लागू किए जा रहे हैं।

उपसभापति जी, जब ये प्रधान मंत्री बने, शायद इनको अलादीन का चिराग़ मिल गया, जिसको घिसते ही बिल्डिंग्स खड़ी हो गईं, सड़कें बन गईं, रेलवे लाइनें बन गईं, एयरपोर्ट्स बन गए, हवाई जहाज उड़ने लग गए, साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतनी उन्नति कर ली कि मिसाइल्स बनने लग गए, यहां तक कि चंद्रयान भी जाने लगे। वह सिर्फ अलादीन के चिराग़ से हुआ। न तो पंडित नेहरू जी ने कुछ किया, न इंदिरा गांधी जी ने कुछ किया, न राजीव गांधी जी ने किया, न नरसिंह राव जी ने किया और न ही इनके वाजपेयी जी ने कुछ किया, जिनको आज तक पूछा नहीं जा रहा है। केवल आज पहली बार जो कुछ किया, वह मोदी जी ने किया। बाकी जो सारा भारत था, बाकी जो सारे नेता थे, वे बिल्कुल आराम से बैठे रहे। उन्होंने 60 साल कुछ नहीं किया। न तो देश को आज़ाद करवाया, न गरीबी के लिए लड़े और न ही भारत को आगे बढ़ाया। आज अगर भारत का नाम है, अगर भारत को पूछा जा रहा था, तो केवल ये कांग्रेस के जो नेता थे, जिनकी विचारधारा थी, जिनकी प्लानिंग थी, उसकी वजह से था, नहीं तो इन लोगों को कोई नहीं जानता था। ये कहां से आये, ये कब थे? न तो ये भारत की आज़ादी में थे, न ही भारत को बनाने में थे, लेकिन आज सबसे ज्यादा अपने आपको भारत की जनता का शुभचिन्तक समझते हैं। हां, हैं शुभचिंतक। महोदय, इन्होंने एक काम किया, जो नोटबंदी कर दी, जो तुगलकी फरमान जारी

* Expunged as ordered by the Chair.

कर दिया, रातों-रात नोटों को कागज के टुकड़े बना दिया, यह जरूर इन्होंने किया है। मैं इस पर नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि इस पर बहुत बोला गया है। सबने कहा है कि इससे कितना काला धन आया, कितनी फेक मनी आई, कितना उग्रवाद रुक गया, इसको सबने बताया है। मैं तो केवल एक बात कहना चाहती हूँ, ये मेरे भाई बैठे हुए हैं, हिन्दू संस्कृति कहती है, जिसके ये बहुत पुजारी हैं, जिसका नाम लेते-लेते ये थकते नहीं हैं, उसी हिन्दू संस्कृति में यह कहा गया है कि बचा कर रखना चाहिए, मुसीबत के समय में काम आएगा। हमारे यहां कुशल गृहिणी उसे कहा जाता था... शादी होने के बाद जब लड़की विदा होती थी, तो मां उसको एक ही सलाह देती थी, बेटी, घर को बनाए रखना, घर के लिए कुछ बचा कर रखना, पति की जो आमदनी होती है, उसको संभाल कर ठीक ढंग से खर्च करना, फिजूलखर्च मत करना, कोई पता नहीं, कब मुसीबत के दिन आ जाएं। मेरी बहनों का वही जो पैसा था, उसको भी इन्होंने काला धन साबित कर दिया। उनको लाइनों में खड़ा कर दिया कि जाओ, अपनी उस संस्कृति का जुलूस निकालो, उसे सरेआम बदनाम करो, आपको पैसा बचाने का कोई हक नहीं है। इसको आपने खर्च नहीं किया, यह आप लोगों का कुसूर है, ये इन्होंने किया, ये इन्होंने बताया।

महोदय, आज जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही है, क्या इसमें उसके बारे में कोई उल्लेख है? इतने बड़े अभिभाषण में क्या उसके बारे में कोई सोच है? बिल्कुल नहीं है। यह इसलिए नहीं है, क्योंकि आप कहते हैं कि चार-चार बच्चे पैदा करो, पांच-पांच बच्चे पैदा करो ताकि वह पढ़ न सके, गरीबी की लाइन में लगा रहे और भिखारियों की तरह सड़कों पर घूमता रहे, उनको शिक्षा नहीं मिल सके। यह आप लोगों की नीति है, यह आप लोगों का माइंडसेट है। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगी कि इस अभिभाषण में कुछ नहीं है, न इन्होंने किया है और न करेंगे। हां, नये-नये नारे जरूर लगा देते हैं, कभी कोई नाम दे देते हैं, कभी किसी के बारे में कह देते हैं। गुरु गोबिन्द सिंह जी की ही बात करते... आप आज इसमें उसका उल्लेख करते हैं, क्योंकि पंजाब में इलेक्शन थे। वैसे इनको उनसे कोई हमदर्दी नहीं है, उनसे कोई लगाव नहीं है। वह गुरु गोबिन्द सिंह जी, जिसने इस देश को बचाने के लिए, हिन्दुओं को बचाने के लिए अपने बच्चों को दीवार में चुनवा दिया था। ये उसका क्या मुकाबला करेंगे, जो इतने-इतने लाखों रुपए के कोट और सूट पहनते हैं, जिनको पता ही नहीं है कि हमें क्या करना है। ये बात करते हैं, ये हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। मैं तो यही पूछना चाहती हूँ कि इन्होंने तीन सालों में किया क्या है? इन्होंने कौन-सा नया काम किया है, कौन-सी नई नीति लाए हैं? विदेश नीति, वह इनकी फेल है। हम चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे पड़े हैं। इनकी आर्थिक नीति फेल है। आज इतना ज्यादा आर्थिक बोझ डाल दिया गया है। जीडीपी के बारे में और वक्ता बता चुके हैं, अभी और भी वक्ता बताएंगे कि आपने इसको कहां से कहां पहुंचा दिया है।

आज विदेशों में जाने के लिए किसान रो रहे हैं, मजदूर रो रहे हैं, मेरी बहनें रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं। आप जिस अमेरिका के लिए बात करते थे, उसी ने आज एचबी-। वीज़ा पर रोक लगा करके ऐसा किया है। जिस टेक्नोलॉजी को, जिस आईटी को राजीव गांधी ने आसमान पर पहुंचाया था और जिसकी वजह से आज हमारी कंपनियों ने विदेशों में अपना स्थान बनाया है, उनको आज बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। यह आप लोगों की नीतियों की वजह से है। वे कहां बोले?

कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक की। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा कि यह तो इवेंट मैनेजमेंट है, गवर्नमेंट मैनेजमेंट नहीं है। यह तो पब्लिसिटी है। आर्मी ने अब तक कितनी ही सर्जिकल स्ट्राइक्स

[श्रीमती विप्लव ठाकुर]

की होंगी, लेकिन कभी उसका शोर नहीं मचा। आपने तो आर्मी को भी मार्केटिग का एक हिस्सा बना दिया, उसको भी बेच दिया। हमारे जो सिपाही, हमारे जो जवान बॉर्डर्स पर लड़ते हैं, अपना खून बहाते हैं, उसका भी आपने पब्लिसिटी के द्वारा मज़ाक उड़ा दिया, अपनी शोहरत के लिए, अपने मुँह मियां मिट्ठू बनने के लिए, अपनी बहादुरी दिखाने के लिए। कहां है वह देशभक्ति? है ही नहीं, क्योंकि देश के साथ कभी प्यार रहा ही नहीं। आप भारत की आज़ादी की लड़ाई में नहीं लड़े, देश बनाने में आपका हिस्सा नहीं रहा। ठीक है, हमारी कुछ गलतियां रहीं, जनता किसी को भी चुन सकती है, किसी को भी वोट दे सकती है। यह उनका अधिकार है और यह अधिकार भी उन्हें कांग्रेस पार्टी ने दिया है, आप लोगों ने नहीं दिया। आज अगर हम वोट देने का हक रखते हैं, इस देश में प्रजातंत्र है, तो कांग्रेस की नीतियों के कारण है। आपका वश चले तो पता नहीं इस देश को कहां ले जाएं! आप लोगों के लिए तो अभी भी डिक्टेटरशिप है, यह खाओ नहीं, यह नहीं पहनो, यहां बैठे रहो, कैबिनेट की मीटिंग में मंत्रियों को बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, मोबाइल यूज़ करने की इजाजत नहीं है। ...(**व्यवधान**)... आप चुप रहिए और सुनिए। जब तक रेडियो में भाषण नहीं कर लेते, टी.वी. में अपना प्रचार नहीं कर लेते, कोई बाहर नहीं जा सकता। जब आपकी पार्टी में ही प्रजातंत्र नहीं है, तो देश में क्या लाएंगे, देश को क्या बनाएंगे?

इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि इस देश की हालत समझिए। किसान की हालत समझिए, गरीब की हालत समझिए, मजदूर की हालत समझिए और महिलाओं की हालत समझिए। आज लॉ एंड ऑर्डर कितना खराब हो गया है। जितने केसेज़ रेप के आज बाहर आ रहे हैं, उतने पहले कभी नहीं आए थे। आप कोई भी स्टेट उठाकर देख लीजिए, कहीं अमन-शांति नहीं है। उनमें एक डर है। अब इन्होंने एक नया शब्द चुन लिया है — देशद्रोही। जो इनके खिलाफ बोल दे, जो इनकी नीतियों की आलोचना कर दे, वह देशद्रोही है। उसे अरेस्ट कर लीजिए, केस चला दीजिए। यह एक नया शब्द इन्होंने निकाल दिया है, एक नई परिभाषा दी है। आपको बोलने का हक नहीं है। यदि आप हां में हां मिलाइए, तो बहुत ठीक हैं। अगर आपने गलत को गलत कह दिया तो आप देशद्रोही हो गए, आपके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए, आपको जेल में डालना चाहिए। आज लोग ऐसे हालात में रह रहे हैं। यू.पी. में तो एक नया काम आपने शुरू कर दिया है। आपका वहां जो manifesto आया है, आप इसे manifesto में क्यों दे रहे हैं, आप कानून बनाइए, कानून को implement कीजिए। कानून eve-teasing के लिए पहले से मौजूद है, उसे ठीक तरह से लागू कीजिए। पुलिस reforms कीजिए। पुलिस को आधुनिक ढंग के हथियार दीजिए। उन्हें ट्रेनिंग दीजिए। ऐसा कानून manifesto में देने से eve-teasing दूर होने वाली नहीं है। आप mindset चेंज कीजिए। सोशल stigma को दूर कीजिए। अपने आपको इससे ऊपर उठाइए। पूरे भारत के बारे में सोचिए। जनता के बारे में सोचिए। केवल नारे मत दीजिए। आपके पास कितनी एफ.डी. आईज़. आ गई हैं? मैंने खुद अम्बाला में देखा है कि किसान आलू की ट्रॉली लेकर डी.सी. के ऑफिस के सामने बैठ जाते हैं कि तुम इन्हें बेचो। आप कहते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, इसका कोई असर ही नहीं हुआ। कितनी लेबर आज अपने-अपने प्रदेशों में वापस चली गई है, इसका सर्वे करके हमें बताइए, फिर पता चलेगा। क्योंकि हम राज्य सभा के सदस्य हैं, हमें जनता से बात नहीं करनी पड़ती लेकिन लोक सभा के मैम्बर्स या एम.एल.ए. से पूछिए कि जनता क्या हाल करती है? आपके ही एक एम.पी. के साथ कैसा व्यवहार हुआ, जो यहीं जनता के बीच भाषण दे रहे थे। लोगों ने कहा कि अंदर आइए और जूतों से पीटा गया कि तुम नोटबंदी की प्रशंसा

3.00 P.M.

करने आए हो, हम इसके कारण आज बेकार हो गए हैं, भूखे मर रहे हैं। इसलिए हकीकत को समझिए और अपने आपको बदलिए। केवल यह मत सोचिए कि यहीं रहेंगे। बड़े-बड़े लोग नहीं रहे, सिकन्दर नहीं रहा, कोई नहीं रहा। हर किसी को जाना पड़ता है। इसलिए अपना समय ऐसी बातों में मत बिताइए बल्कि भारत के लिए कुछ कीजिए, यहां की जनता के लिए कुछ कीजिए। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करती हूं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you very much. Now, Shri S. R. Balasubramoniyan; not present. Shri Narendra Kumar Swain; not present. Shri C. M. Ramesh; not present. Shri K. T. S. Tulsi.

SHRI K. T. S. TULSI (Nominated): Hon. Deputy Chairman, Sir, I thank you for giving me an opportunity for speaking on the Motion of Thanks on the President's Address. While listening to the speech of the hon. President, I was waiting to hear a word of concern or sympathy with regard to the catastrophic impact which demonetisation policy of the Government, had in the country. The effect of demonetisation was vastly felt in the areas of employment as well as industry. However, the deafening silence in the Address is a matter of great concern. There was not even a word of condolence to the families of those, over a hundred, who lost their lives while standing in the queues to withdraw money from the ATMs. I just fail to understand as to what would have caused this kind of a catastrophe. It is said that the design of the new notes was finalised on 19th May, 2016. If the design was finalised on 19th May, what prevented the Government from printing the notes? What prevented the Government from recalibrating the ATMs? This is a tragedy in which over a hundred lives were lost, but no one is sorry about the catastrophic effect or even the loss of lives of our countrymen. There is no assurance of employment to the families of those who died, because the Government does not want to acknowledge the fact that people have died standing in the queues. There is no compensation, there is no assurance of employment and there is nothing in this Address which gives an assurance with regard to the revival of industries which have shut down. The Government promised two crore jobs every year. Instead of providing jobs, what has happened is that millions of jobs have been taken away from the people who were gainfully employed.

According to the Fifth Annual Employment-Unemployment Survey conducted in October, 2016, the unemployment rate was the highest in five years. If unemployment rate was already the highest in five years, then, one can imagine the impact of losing 6 lakh further jobs, which have been lost as a direct result of demonetisation policy.

The Survey also states that about 77 per cent of the rural households have no regular income and earn a monthly income of less than ₹ 10,000/-. This is the

[Shri K. T. S. Tulsi]

Survey which was conducted by the Labour Bureau, which comes under the Labour Ministry. Was the Government unaware of such a distressful situation of employment? Why at that very moment, it adopted the demonetisation policy?

[THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA) *in the Chair*)

The economic growth of a nation is decided by the rate of employment in the country. The Address does not, unfortunately, mention as to how the industrial sector has been hit by demonetisation. For example, Ludhiana hosiery industry which provides employment to around 4,00,000 people, and about 70 per cent of its industrial units has shut down.

The Address mentioned Swachh Bharat Abhiyan and claimed that more than three crore toilets had been constructed, but it did not mention how many of these toilets were functional. The National Sample Survey Office revealed that in 2016-17, only 46 per cent of the 95 lakh toilets, which were built, are usable. Therefore, there cannot be a more classic example of wastage of taxpayers' money than this. This also amounts to a breach of promise and a breach of faith and misleading the country that this was, in fact, to rake out the black money. Black Money is not kept in cash. Everybody knew that. In fact, they have turned every Indian into a criminal that if you have cash, your cash is going to be confiscated and you have to stand in the queue and you cannot even withdraw your own money. This kind of a spectacle has not been seen in India after Partition.

The Government claims that the outlay for Railways has been increased. But it does not mention that hundreds of lives have been lost in never-ending accidents of the trains on account of lack of safety on the tracks. I hope that they will not launch a bullet train on these tracks which cannot even take a speed of 60 kilometres.

I wish the Address would have mentioned as to how many *jawans* have been killed on the borders after surgical strikes and how their families are getting along and whether any of them has been either assured a job or been compensated. Failing to mention the sacrifices of our *jawans*, in fact, belittles their martyrdom. I did not find a word of concern as to how farmers are eking out a living when they are not even getting a minimum price for their crops.

All in all, I feel that the Government needs to introspect and examine their failure in the field of industry, agriculture and employment. Thank you.

श्री राम कुमार कश्यप (हरियाणा) : उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में सरकार की एक साल की उपलब्धियों पर ही चर्चा की

है। उसमें इतनी योजनाओं की विस्तार से चर्चा की गई है, उससे तो ऐसा लगता है कि हमारा देश बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा है, परन्तु वैसा नहीं है। दावों को हकीकत के साथ जोड़ कर भी देखना होगा। अभिभाषण में नोटबंदी की भी बात की गई है। उसमें कहा गया कि नोटबंदी से काला धन, भ्रष्टाचार, जाली करंसी और आतंकवादियों को धन मुहैया कराने जैसी बुराइयों का अंत होगा और राष्ट्रपति जी ने सरकार के इस कदम की सराहना भी की है, परन्तु ऐसा नहीं है। अब कितना काला धन आएगा, भ्रष्टाचार कम होगा, कब होगा यह तो भविष्य की बात है, क्योंकि "In the long run we are all dead", अर्थशास्त्री केन्स ने ऐसा कहा है।

अब मैं वर्तमान की बात करता हूं। जब मैं वर्तमान की बात करता हूं तो नोटबंदी से हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा दुष्पभाव पड़ा है। जनता को बहुत तकलीफों को सहन करना पड़ा, लम्बी-लम्बी लाइनों में लगकर उनको बैंकों में अपने नोट जमा कराने पड़े, पैसा निकलवाना पड़ा। इससे देश में लगभग 135 लोगों की जानें चली गईं। हमारे देश के बाद वेनेजुएला में भी नोटबंदी का काम किया गया। परन्तु वहां पर जनता ने सरकार का सहयोग नहीं किया। 72 घंटे में ही वहां की अर्थव्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई, लोग सड़कों पर आ गए, सारी दुकानें लूट ली गईं, जिस कारण सरकार को एक हफ्ते बाद अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। परन्तु हमारी जनता ने ऐसा नहीं किया और सरकार के नोटबंदी के निर्णय को हौसले से स्वीकार करके तकलीफें सहकर भी काम किया। इसके बारे में मैं केवल इतना कहना चाहूंगा और सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि जिन 135 निर्दोष लोगों की जानें चली गयी हैं, सरकार उनके संबंध में सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उनके परिवार को रोज़गार देने या उनकी आर्थिक सहायता करने का काम करे। मैं यह बात इसलिए नहीं कह रहा हूं कि नोटबंदी के समय नोट लेते हुए उनकी जानें चली गयीं, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि हमारे देश के विकास में, राष्ट्र निर्माण में हरेक नागरिक का अहम योगदान होता है, चाहे वह गरीब है या अमीर, चाहे कर्मचारी है या व्यापारी। वे लोग, जो मारे गए, वे भी देश के निर्माण में कहीं न कहीं काम कर रहे थे, उनका भी राष्ट्र के निर्माण में योगदान है, इसलिए मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि उनके परिवारवालों को रोज़गार मुहैया कराया जाए और उनको compensate करने का काम किया जाए।

दूसरा, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" कार्यक्रम का भी उल्लेख किया गया है। सरकार के द्वारा यह कार्यक्रम लिंग अनुपात में सुधार करने के लिए चलाया गया। सरकार का यह कदम सराहनीय है, लेकिन इसमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। आज हमारे देश में लड़कों के अनुपात में लड़कियों की संख्या घटती जा रही है। अगर मैं सन् 2011 की जनगणना का यहां पर उल्लेख करूं तो सन् 2011 में भारत में 1,000 लड़कों के पीछे 943 लड़कियां थे। जो हमारे भारत के समृद्धिशाली प्रदेश हैं, जैसे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, गुजरात और यूपी, उनमें तो स्थिति बहुत ही भयानक है। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो वहां सन् 2011 में 1,000 लड़कों के अनुपात में 879 लड़कियां थीं, पंजाब में 1,000 लड़कों के अनुपात में 895 लड़कियां, दिल्ली, जो बहुत समृद्धिशाली प्रदेश है, यहां 1,000 लड़कों के अनुपात में 868 लड़कियां, गुजरात में 1,000 लड़कों के अनुपात में 919 लड़कियां और उत्तर प्रदेश में 1,000 लड़कों के अनुपात में 912 लड़कियां थीं। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे समाज में लड़कों को ज्यादा और लड़कियों को कम तरजीह दी जाती है। इसके अलावा आज हमारे देश में भ्रूण हत्याएं बहुत हो रही हैं। एक समाचार पत्र के अनुसार अब तक देश में तीन मिलियन भ्रूण हत्याएं हो चुकी हैं। उन लड़कियों को गर्भ में ही मार दिया गया है, उन्हें अपनी मां का मुंह तक नहीं देखने दिया

[श्री राम कुमार कश्यप]

गया। यह बहुत शर्मनाक बात है। इसके लिए सरकार को कुछ करना होगा। इसमें जनता का भी सहयोग अनिवार्य है और सरकार को भी इसमें बहुत कुछ करना होगा। सर, मैं "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" में एक शब्द और जोड़ना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि बेटी को बचाने और पढ़ाने के अलावा उसका सम्मान भी करना होगा इसके लिए इसमें "बेटी बधाओ" भी जोड़ना चाहिए। यह गुजरात का शब्द है, "बधाओ" का मतलब है कि बेटी का मान-सम्मान भी करना होगा और उसे पढ़ाना भी होगा। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने के लिए लड़कियों का मान-सम्मान किया जाए, क्योंकि लड़कियां हमारे लिए लड़कों से कम नहीं हैं।

महोदय, अभी ओलम्पिक गेम्स हुए। वहां पर हमारे देश से 117 खिलाड़ी खेलने के लिए गए। यह बड़ी खुशी की बात है कि वहां पर दो लड़कियों ने ही हमारे देश के मान-सम्मान को आगे बढ़ाया, दो लड़कियां ही हैं जो वहां से मैडल लेकर आयी हैं, इसलिए लड़कियों के लिए कुछ करना होगा। मैं कहना चाहूंगा कि भ्रूण हत्या को रोकने के लिए इसे जघन्य अपराध की श्रेणी में लाया जाए। जो सजा जघन्य अपराध करने वालों को दी जाती है, चाहे वह फांसी की सजा हो या उम्र कैद की, वही सजा उन्हें भी मिलनी चाहिए जो भ्रूण हत्या करता है।

बेटियों के सम्मान के लिए मैं केंद्र सरकार से आग्रह करूंगा कि केंद्रीय सरकार को भी इसमें पहल करनी होगी। केंद्र सरकार की तरफ से एक circular जारी कर दिया जाए कि जब कोई महिला या लड़की किसी केंद्रीय कार्यालय में जाती है तो कर्मचारी या अधिकारी, जो वहां पर उसे मिलते हैं, वे खड़े होकर उसका मान-सम्मान करें और फिर उसके बाद वे सब अपना काम करें।

इसके अतिरिक्त आज जिन परिवारों में लड़कियां ही लड़कियां हैं, लड़के नहीं हैं, उनके संबंध में मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि उन लड़कियों का भी मान-सम्मान करना होगा, उनके लिए भी हमें कोई योजना बनानी होगी। मेरा सरकार से आग्रह है कि ऐसे परिवार, जिनमें लड़कियां ही लड़कियां हैं, उन लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में admission के समय और नौकरियों में भी वरीयता मिलनी चाहिए। मेरा मानना है कि जब ऐसा होगा तो भ्रूण हत्या जैसी बुराइयां दूर हो जाएंगी।

तीसरा, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में एक बहुत अच्छी बात कही गयी कि लोक सभा और विधान सभा के चुनाव इकट्ठे कराए जाएं। मैं इससे सहमत हूं क्योंकि जब बार-बार चुनाव होते हैं तो उसमें बहुत धन खर्च होता है। इसके अतिरिक्त जो हमारे कर्मचारी भाई हैं, बहुत अधिक संख्या में उनकी वहां पर ड्यूटी लगानी पड़ती है। मैं इसमें केवल इतना कहना चाहता हूं कि इससे जो पैसा बचेगा, उससे हमारे देश को काफी लाभ होगा क्योंकि हमारा देश एक गरीब देश है। हमारे देश में आज भी 40 परसेंट जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे रह रही है। यहां पर बेरोज़गारी की समस्या है। आज पीएचडी किए हुए लड़के-लड़कियां आंगनवाड़ी वर्कर की पोस्ट पर लगने के लिए तैयार हैं, इसलिए चुनाव एक साथ हों — यह एक अच्छा कदम है। मेरा सुझाव है कि सभी पार्टियों को विश्वास में लेकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। इससे जो पैसा बचेगा, उस पैसे को गरीबी दूर करने के कार्यक्रम में लगाया जाए या बेरोजगारी को दूर करने के कार्यक्रम में लगाया जाए। आज हमारे देश में बेरोजगारी बहुत भयानक रूप ले चुकी है। इसलिए मैं कहूंगा कि उस पैसे से हरेक स्टेट में या हरेक जिले में बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगायी जाएं। जब देश में इंडस्ट्रीज़ लगेंगी, तो उनसे रोजगार बढ़ेगा, गरीबी दूर होगी, ऐसा मेरा मानना है।

अंत में, मैं कहना चाहता हूं कि किसानों के बारे में अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। आज हमारे किसान बहुत दुखी हैं। हमारे किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिलता है। इसलिए किसान बहुत पीछे चले गए हैं। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर किसानों को बचाना है, तो सरकार को किसानों के कर्ज माफ करने होंगे। अंत में, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद करता हूं, जय हिन्द, जय भारत।

SHRI T. K. S. ELANGOVAN (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, while thanking His Excellency for addressing the Joint Session of this Parliament, on behalf of the DMK, I want to register certain points.

Sir, my first assessment of this Address is that it has made many mountains out of the molehills. All small things have been exaggerated to big things. As a first case, I can quote from the Address, "Financial inclusion is key to poverty alleviation. So, 26 crore plus Jan Dhan accounts have been opened for the unbanked." Sir, opening bank accounts will only add the names of these people in the bank ledgers. It cannot be termed as financial inclusion. Financial inclusion means they should have the finance to operate their accounts. At least, 40 to 45 per cent of these accounts are dormant or inoperative. So, merely opening accounts in a bank does not mean that it is financial inclusion; it is only inclusion of their names in the bank ledgers. Beyond that, there is nothing that they can claim.

Secondly, Sir, I want to quote the recent report by Oxfam on the economic inequality in India. The Report says, "Fifty-seven millionaires in India possess as much wealth as is possessed by the poorest 70 per cent of the country." The wealth of the 70 per cent of the poor is equivalent to just 57 citizens in India. The Report further says that the Government lost tax and valuable income with the super-rich depositing their wealth in tax havens abroad and manipulating political systems to do so without repercussion. This observation was found in the Oxfam Report. All I want to say is that the Government must promise to bring back the black money invested in foreign countries. Since they could not do so, they want to show off; they want to present a picture that this Government is against black money and they have taken up this demonetization exercise. I can say, Sir, that out of the total population of this country, 69 per cent people are agriculturists. We know that agricultural income does not attract Income Tax. About 6 to 7 per cent people are fishermen. We know that fishing income does not attract Income Tax. Remaining 15 to 16 per cent are monthly salaried classes. In that also, seven per cent people have paid tax. The remaining people, whose income does not fall under the threshold of taxation, that is, it is less than ₹ 3 lakhs, will also not pay tax. Only 7 to 8 per cent of population of India hold heavy money. We have a proverb in Tamil, "*Mootaipoochikku bayandhundu veettai koluthardhu.*" This means, 'burning

[Shri T. K. S. Elangovan]

the house to kill the bed bugs'. That is what this Government has done. They have burnt the house to kill the bed bugs. Beyond that, there is no fruitful purpose of this exercise. This is only to hide the Government's failure in bringing back the black money from overseas to India. It was the promise made during the elections and the Prime Minister had assured that this was his prime priority. Sir, there are many other things. I come to Swachh Bharat Cess. The local bodies are directly involved in the cleanliness of the cities. I do not know how much of the cess collected by the Government of India as Swachh Bharat Cess is given to the local bodies.

Sir, there is one issue about the simultaneous elections. It is a serious issue, which is being discussed on various fora. First thing is that simultaneous election is possible only in a two-party democracy. We are a multi-party democracy. Secondly, if we are following First Past the Post system in declaring a candidate as elected, if it is proportional representation, then also, simultaneous election is possible.

Sir, in 1996, we had parliamentary elections; in 1998, once again, we had parliamentary elections; and, in 1999, again, we had parliamentary elections. When the Parliament is dissolved, can we dissolve all the assemblies and conduct simultaneous elections? It is not possible. The system has to change. You must have, at least, proportional representation in election so that simultaneous elections can be possible.

I would like to appreciate certain things in the President's Address because they have followed the steps which our party leader Dr. Kalaignar took when he was the Chief Minister of Tamil Nadu. In 1974 itself, Tamil Nadu had 100 per cent rural electrification. Women Self-Help Groups were formed in the year 1989 when our leader was the Chief Minister of Tamil Nadu. Slum Clearance Boards and Group Housing Schemes were started. Subsequently, the Group Housing scheme which was started in Tamil Nadu was followed up by the Government of India and was called Indira Awas Yojana. It was appreciated by Dr. Jayaprakash Narayana himself.

Sir, we gave free gas connections to the rural poor in the year 1996. Some of the things, which we did in Tamil Nadu long back when the DMK was in power, appear in this President's Address. It is a welcome measure. Otherwise, this Address can be termed as 'making mountain out of mole hills'. With these words, I conclude.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Now, Shri K. C. Ramamurthy.

SHRI K. C. RAMAMURTHY (Karnataka): Mr. Vice-Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity, privilege and honour to make my maiden speech on the Motion of Thanks on the President's Address. Before I proceed further, I would

like to express my deep sense of gratitude to my party President Shrimati Sonia Gandhi ji, party Vice-President, Shri Rahul Gandhi ji and other senior leaders of the party at the Centre and the State. I also take this opportunity to seek guidance and help from the senior leaders of not only my party but of the entire House in discharging my duties in my journey as a Member in this House.

Now, the primary objective behind the Address of the hon. President to both the Houses of Parliament is to present the vision of the Government for the forthcoming years. But this year's Address appears to be trumpeting the schemes, programmes and day-to-day working of the Government rather than giving details as to what the Government is going to do in the coming years. Sir, I feel that the Address is monotonous, visionless, insipid and no less than run of the mill. Nothing is mentioned about internal security and the problems of the police personnel. Many of the hon. Members have spoken at length on various aspects. I do not wish to repeat that. With your kind permission, Sir, I wish to concentrate only on a very important and dearer subject to me, the police reforms, which is not only sensitive and important but also having far-reaching consequences. Sir, I would like to mention here that our hon. Prime Minister, while addressing the Director Generals of Police in Guwahati in 2014, envisaged the concept of SMART police. The hon. Prime Minister had given a unique definition to police which would be strict and sensitive for 'S', modern and mobile for 'M', alert and accountable for 'A', reliable and responsible for 'R' and technosavvy and trained for 'T'. Since then, the entire country, the entire police force has been looking for transformational change, and it has been more than two years but the SMART police remains only on paper and reduced to a *jumla*. So, I wish that the Government of India, instead of giving slogans, should do something concrete in the area of police reforms.

Sir, when we talk of police reforms, I would like to mention here that without proper and effective internal security, progress of the state is not possible. There can be a situation where a serious lawlessness can prevail in the country if police reforms are not taken up in a very, very serious manner. Sir, I have mentioned about police reforms. The police is put to scrutiny every minute by everyone. It can be all of us politicians, it can be establishments; everyone wants to put the police to test. They like to point finger at the police for all the misdeeds committed by so many people. All that is pointed towards the police and the police is held accountable everywhere.

But, unfortunately, when it comes to reforming the police and making them strong and effective, no action, as such, has been taken by anybody. Sir, when it comes to reforms, I would like to concentrate on two aspects — one is manpower reforms and the other is police station reforms or functioning of the police reforms.

[Shri K. C. Ramamurthy]

When it comes to manpower reforms, I would like to say about the wages that the police get, in *Kannada* they call it *Kanishtha Bille*. I hope my friends here from Karnataka will understand. *Kanishtha Bille* is the least amount. The police get the least salary that a Government servant gets. That was the situation. Of course, in Karnataka, the situation has improved a lot and the police are treated at par with other Government servants. But what I want to mention here, Sir, is that the wages to the police force, wages to the policemen, wages to the police system should not be clubbed with any other Government department. The situation is different; the work function is different; the activities are different. So, they must be on a different level. Their wages should be totally based on the risk factor, based on the efforts that they put in and based on the other activities which they are supposed to perform. Sir, they don't have bargaining power. They are a disciplined force. They cannot even walk to *Jantar Mantar* raising their demands. Never can they do it; never have they done it. They are helpless. Ninety-two per cent of the police force comprises head constables, constables and assistant subinspectors. Sir, they are voiceless. Who is to take care of them? It is the Government who should look at it. Both the State and the Central Governments should look into this issue very, very seriously. If they are not taken care of, if they are not looked after, if they are not taken into confidence, how can they discharge their duties? What efficiency can we expect from them?

Sir, the recruitment process is very bad. I am talking this out of my personal experience. Sir, at a given point of time, there are 25 to 30 per cent vacancies in the police force. 25 to 30 per cent vacancies, and everybody expects, the public expects, the Government expects, police to be very, very efficient, honest and all that. But, how can they discharge their duty, how is it possible with 25 per cent vacancies in the police force? With the 25 to 30 per cent police posts vacant, they are not able to allot duties properly, they are not able to get leave, they are not able to get their weekly offs, they are not able to enjoy even a single day with their families. All of us here celebrate our festivals. When all of us celebrate festivals and other ceremonies, police are there to give us protection. They are not able to go to their homes to celebrate festivals with their family members. This is the utmost sacrifice that anybody can make. The police are doing this. And what are we doing for them? What are we thinking about them? Absolutely nothing.

I would like to mention here that once a policeman is recruited, he never gets trained again. Not many States have a system of training policemen often or equipping them with the knowledge of latest laws or new weaponry. In the current situation, we see a policeman with a *lathi*. That is the maximum that he gets. He

is the person who is supposed to face terrorists. He is the person who is supposed to face naxals. He is the person who is supposed to face anti-national elements. He is the person who is held responsible for anything that happens in the police station. And what is it that we are doing for them? Sir, there is nothing that we are doing for them. I would like to mention here that hardly any training is given to a policeman again after he is recruited. The Central Government must think of a system to give them training just like the IPS Officers go for refresher courses at every level whether middle or higher. At every level, we have programmes. We go and interact with other officers and people in the entire country and understand a lot of things. A police constable or a head constable or an ASI or SI or an Inspector hardly gets any training again after joining the service. Whatever they learnt in the Police Training Schools or Police Training Colleges, that's the end of it. They don't have any training facilities later.

One very important aspect, which I would like to mention, is about their housing. Police constables or head constables in urban areas particularly do not get private houses on rent. Private housing is not possible for them. A policeman is the least preferred person when it comes to getting a house on rent. There are only 5.8 lakh houses as against the requirement of 17.3 lakh houses. Where should the remaining policemen go? People do not give them their house on rent. They are not recognised. They are socially unacceptable. They have to live in slums. I have personal knowledge of it. They travel from far-off places, from slum areas, to perform their duty in the city and go back in uniform to their houses in the evening. This is the situation. Their housing should be given a priority. It is very unfortunate that this Government, or any Government for that matter, has not taken police reforms very seriously. Nothing about it has been mentioned in the President's Address or in the Budget. The allocation for police itself is very, very poor. It is insufficient.

When it comes to police station, we have seen a lot of buildings, which house them. Police stations have been attacked many times and policemen have been killed in the police stations. Police are robbed of their weapons in the police station. What about the safety of the police stations? How bad these buildings been constructed? In most of the places, the buildings are very, very small. Some of them are like huts. These buildings are not safe. A police station is a place where when public goes, should feel as if they have gone to a place where they can get justice. There is no place for them to sit. There is no furniture. There are no facilities like toilets, visitors room, waiting room at all. The policemen, who don't have their own houses, stay in the police station. That also becomes a resting place for them. Imagine the space available for police duties? We need to concentrate on this aspect very seriously.

[Shri K. C. Ramamurthy]

The equipment there in the police station is outdated. Sir, all of us are aware that the criminals are now having fastmoving vehicles. They have got the best of weapons. They have got most modern gadgets with them to deal with other criminals. But what is it that the policemen are having in police stations? Absolutely nothing. Can we be confident of the internal security of our country if we don't strengthen the hands of police? If you don't take this matter seriously, will we be able to safeguard our internal security? Sir, I feel there is imminent danger to it. The danger is not far away from us. It is near us very close to us. Unless we take up police reforms very seriously, our internal security may collapse any time. I have mentioned about weapons and latest gadgets which need to be updated and properly equipped.

Now, I come to police welfare measures. Sir, there is one very sad thing. what is called benevolent fund. It must be or may be there in all the States. Sir, who contributes to the benevolent fund? Policemen themselves will have to contribute for their own welfare. Every policeman will have to contribute ₹ 25; a Head Constable contributes ₹ 50; an Assistant Sub Inspector contributes ₹ 100 and like that, every month, they will have to contribute. Out of that, their welfare activities take place. Is this what we want to do for police welfare? Policemen and officers try to organize some cultural programmes, benefit shows and collect some money and through the money collected, they try to educate their children, and try to get some medical assistance. It is totally insufficient and it is a very bad system. Governments, both central and States should contribute regularly for police welfare fund.

Sir, as I mentioned, the wages for policemen need to be fixed separately. They need not be compared with other Government servants when their wages are fixed. Risk factor, weekly offs, holidays, etc. need to be taken into account. Sir, anywhere else, the human rights would have come into effect. We need to see the way the police people are treated and the way the police stations are functioning. If the same situation existed in any other place, human rights violation would have come into the picture long back. People would have been prosecuted for doing these things. But, there is no voice for the policemen. They are silently suffering. I would like this House to take note of these problems of policemen and see that some activities, which help the police to improve their morale and improve their economic conditions, are taken up.

Sir, I would like to mention here that from 1961, thirty thousand policemen have lost their lives in performing their duties. I have the greatest respect for the Armed Forces. I am not comparing them in any manner. But, a number of policemen have died in the line of duty. As our friends were mentioning, are the people who died, while standing in queues, not human beings? The same treatment is given to police. These 30,000 people have died and the number is increasing every year. We have

the Police Commemoration Day on 21st October. Sir, who attends that function? It is only retired police officers. Public is not concerned about it. There is still that colonial attitude and colonial thinking about police stations and policemen. It is still very deeply rooted in the mindset of our people. That should change. Sir, I feel – I do not know why it has not been done so far – policemen who die on duty should be treated as martyrs. Why are they not treated as martyrs? They have lost best of their lives, they have sacrificed so much and they died on duty. Why should not they be treated as martyrs? I think we should treat the policemen who die on duty as martyrs. Supreme sacrifice of police goes unnoticed due to indifference shown by polity, media, society and other established institutions. Sir, if the society does not recognise them, if the society does not take care of them, if the Government does not take care of them and if we do not take police reforms seriously and see that something is done, then, serious impact will be there in the society and its impact on serving policemen will be too much. ...(*Time-bell rings*)... Sir, this is my maiden speech. I thought I would get some more time.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Fifteen minutes are over.

SHRI K. C. RAMAMURTHY: Sir, please give me five more minutes. Sir, I would like to briefly mention about public-police relationship. The mindset of the public needs to change. It is not that it will change just like that. But, efforts towards that have to be made by various agencies. There is nothing mentioned anywhere in the entire Budget Speech or in the Presidential Address about reforms in police force. Nothing is spoken about these very, very important aspects which will have a detrimental effect on the society. If the internal security is proper and if the internal security is strong, the economic development will take place and the society will be peaceful. If that is not there, nothing can be done and nobody can save the country. It will become very, very difficult and impossible. Sir, I would like to mention in conclusion that I want this House to ponder over and think of those policemen and officers who stay away from their near and dear ones on all important festivals, on all important celebrations only to ensure that all of us happily celebrate them.

I would like this House and the society to think of those policemen and officers, who face criminals, anti-social elements, terrorists, naxals, either unarmed or ineffectively armed or less in numbers. They will not hesitate to go and face them. They will not hesitate to get injured or get killed. They are doing their duty.

I would like this august House to see that the message of the police wellness is well-taken and spread and not use police for political ends, not use police for personal ends. That will not serve any purpose. Unless we take care of our policemen,

[Shri K. C. Ramamurthy]

they will not be able to take care of the country. All that they require is public acknowledgement of their work, of their sacrifice and suffering. They need to be encouraged. For them to do better, we should stop using police for all personal gains. This, I think, should start from this House.

It should become the primary duty and priority of the Central and State Governments to properly take care of most important so-called strong arm of the Government. If the strong arm, for example, becomes weak, useless and ineffective, the outcome is left to the imagination of the House.

There is a strong feeling that police are very corrupt. I do not deny the fact that there are black sheep in police also just like in any other department. But, I feel, 90 per cent of the police force are sincere and hardworking. 10 per cent black sheep are there and because of the 10 per cent the entire Department cannot be painted red. Because of the 10 per cent they cannot say that police are bad. It is the duty of the Government to identify the black sheep, to take action against them, improving the 90 per cent to 95 per cent or 98 per cent. That action should be taken. It is like any other department but they are more visible because of the uniform.

Suppose a policeman is walking in Connaught Place. Even if some hundred rupees skip from the pocket of a policeman in uniform slips and falls and if he picks it up, a hundred people will watch and think that somebody has given money and he is picking up. This is the mindset of the people. That should change, Sir. I wish that 90 per cent who are good in the police are recognised, respected and taken care of. Thank you very much for the opportunity given to me, Sir.

श्रीमती विप्लव ठाकुरः सर, एक मिनट। यहां कोई ऐसा नहीं लग रहा, जो हम लोगों के points को लिख रहा हो। यहां ऐसा लगता है कि कोई serious नहीं है। हमने नहीं देखा कि लोग बोल रहे हैं और कोई लिख रहा है, तो प्रधान मंत्री जी हमारे points का क्या जवाब देंगे? यहां पर कोई भी नहीं है।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया)ः मिनिस्टर साहब यहां हैं।

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION (SHRI ASHOK GAJAPATHI RAJU PUSAPATI): There is attendance here, Sir. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Yes. It is visible. सभी दिखाई दे रहे हैं। महंत शम्भुप्रसादजी तुंदिया।

महंत शम्भुप्रसादजी तुंदिया (गुजरात)ः आदरणीय उपसभाध्यक्ष जी, महामहिम राष्ट्रपति जी ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को सम्बोधित करते हुए भारत के आदरणीय प्रधान मंत्री, नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व वाली भाजपा सरकार द्वारा एक सशक्त भारत के निर्माण की दिशा और दशा के सम्बन्ध में उठाए गए क्रांतिकारी कदमों की जानकारी हमें दी, जिसमें

किसानों, महिला, युवा वर्ग और गरीबों के लिए जो योजनाएँ रखी गईं, वे बहुत ही उत्साहवर्द्धक हैं और अत्यंत ही सराहनीय हैं, क्योंकि इसमें 'सबका साथ और सबका विकास' को मूल मंत्र बना कर इसको सकारात्मक ढंग से सार्थक करने का प्रयास दिख रहा है। माननीय उपसभाध्यक्ष जी, वैसे तो अनेक दिशाओं से सभी क्षेत्र के विभागों में बहुत ही सराहनीय एवं विकासशील बातें आई हैं, मगर मैं सभी बातों के ऊपर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित एवं श्रमिक वर्ग से जुड़ी हुई जो बातें हैं, उन विषयों के ऊपर ज्यादा ध्यान देकर उस संदर्भ में बात करना चाहता हूँ। सर, वर्ष 2016-17 के बजट के आवंटन की तुलना में इस साल के बजट में 35% की बढ़ोतरी की गई है। अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 2016-17 में 38,833 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जिसे बढ़ा कर इस साल के बजट में 52,393 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी का व्यक्तिगत रूप से बहुत आभार प्रकट करता हूं।

सर, महामहिम जी के अभिभाषण पर बोलते हुए इस सदन के कुछ सदस्यों ने अपनी बातें रखी थीं, जिनमें खास तौर से आदरणीय शरद जी और आदरणीय सीताराम जी ने कहा कि दलितों, वंचितों और पिछड़ों के लिए इस अभिभाषण में कहीं कोई जिक्र नहीं है।

सर, मैं सदन के सामने इस संबंध में अपनी बात रखना चाहता हूं। आज़ादी के 70 साल के बाद पहली बार इस देश को एक ऐसा प्रधान मंत्री मिला, जिसने यह कहा कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित है। प्रधान मंत्री ने आदरणीय पंडित श्री दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मशती के उपलक्ष्य में इस वर्ष को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मानने की घोषणा की गई है। सर, पिछले अढ़ाई साल में पहली बार इस प्रकार के काम किए गए हैं। आदरणीय प्रधान मंत्री, श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली इस सरकार ने दलितों एवं पिछड़े वर्ग के लिए कई योजनाएं रखी हैं। दलितों के मसीहा और पूरे विश्व के रत्न गिने जाने वाले आदरणीय बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर जी की 125वीं जन्म जयन्ती के उपलक्ष्य में पहले भी बहुत कुछ कहा जाता रहा है, लेकिन पिछले अढ़ाई साल में जो हुआ है, उसका मैं यहां कुछ उल्लेख करना चाहता हूं। भारत के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उनकी शिक्षा भूमि लन्दन में 10 किंग हेनरीज़ रोड की इमारत को खरीदा गया और वहां पर भव्य स्मारक बनाने की बात रखी गई। कांग्रेस के शासन काल में भी उस इमारत को बेचने का समाचार निकला था, परन्तु कांग्रेस ने इसको खरीदने का कोई भी प्रयास नहीं किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको खरीद कर वहां एक भव्य स्मारक बनाने की बात की है। वहां स्मारक बनने के बाद, पढ़ाई के लिए भारत से लन्दन जाने वाले पिछड़े वर्ग के जितने छात्र हैं, आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने उनके लिए आवास और बुनियादी सुविधाएं दिए जाने का बंदोबस्त ने किया है।

दूसरा, बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर जी की 125वीं जन्मशती के उपलक्ष्य में उनके परिनिर्वाण दिवस पर 125 रुपये एवं 10 रुपये के सिक्के जारी किए गए। बाबा साहेब डा. अम्बेडकर जी ने नाम से डाक टिकट जारी किया गया, साथ ही दिल्ली के 15 जनपथ पर स्थित, डा. अम्बेडकर प्रतिष्ठान का शिलान्यास आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद किया। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अध्ययन केंद्र बनाए जाने हेतु 200 करोड़ रुपये का प्रावधान करके हमने बाबा साहेब डा. अम्बेडकर को सच्ची श्रद्धांजिल अर्पित करने का प्रयास किया है।

महोदय, अगर मैं इससे आगे की बात करूं तो महाराष्ट्र के दादर में स्थित उनकी चैत्य

[महंत शम्भुप्रसादजी तुंदिया]

भूमि को विकसित करने का निर्णय लिया गया है। महाराष्ट्र के ही चिंचौली, नागपुर को विकसित करने का निर्णय लिया गया है। गुजरात में, जहां से मैं आता हूं और जहां डा. भीमराव अम्बेडकर जी को बड़ौदा के नरेश, महाराजा शिवाजी राव गायकवाड़ जी ने स्कॉलरशिप देकर पढ़ाई के लिए भेजा। पढ़ाई करने के बाद उन्होंने अपना काम करना शुरू किया, लेकिन तभी उनको कुछ अनुभव प्राप्त हुआ, जिसके आधार पर उनके मन में यह संकल्प पैदा हुआ कि मैं अपने समाज के लिए काम करूंगा। उस समय उन्होंने, बड़ौदा शहर में एक पेड़ के नीचे बैठ करके समाज के उद्धार के लिए संकल्प लिया था, लेकिन आज तक किसी ने उस पेड़ की कोई चिंता नहीं की थी। आज उस संकल्प भूमि पर, जहां डा. भीमराव अम्बेडकर जी के मन में दलितों के उत्थान के लिए संकल्प उभरा था, उनकी 125वीं जयन्ती के उपलक्ष्य में, बाबा साहेब डा. अम्बेडकर के नाम से गुजरात की सरकार ने 125 करोड़ रुपये का प्रावधान करके एक बड़ा स्मारक बनाने का संकल्प लिया है।

तीसरा, मैं आपको आगे और भी बताना चाहूंगा। दिल्ली के 26, अलीपुर रोड पर स्थित उनकी परिनिर्वाण भूमि पर, 100 करोड़ की लागत से, संविधान के आकार वाली एक बहुत बड़ी इमारत बनाकर देश की जनता को समर्पित की जाएगी।

सर, यहां इस विषय पर भाषणों के दौरान कहा गया कि देश में दलितों के लिए कुछ नहीं किया गया है, ऐसा कहना ठीक नहीं है। मैं यहां दलितों के बारे में जितनी बातें गिनाऊं, वे कम लगती हैं। मैं यदि इस बारे में पूरा संदर्भ लेकर बातें कहूं तो बहुत समय लग जाएगा।

महोदय, संविधान दिवस पर, पहली बार डा. बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से सदन में दो दिवस की चर्चा रखी गई और उसमें आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने घोषणा की थी कि डा. भीमरावराम जी अम्बेडकर के नाम से हमने 'पंच-तीर्थ' का निर्माण किया है। मैंने अभी जिन चीजों का नाम लिया जैसे — शिक्षा भूमि लंदन, चैत्य भूमि, संकल्प भूमि, परिनिर्वाण भूमि आदि के लिए सरकार की ओर से पहली बार किसी के लिए 100 करोड़ रुपए, किसी के लिए 125 करोड़ और किसी के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान कर के और उनके नाम से स्मारक बनाकर सही रूप से उन्हें श्रद्धांजिल अर्पित करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में श्री नरेंद्र जी भाई की सरकार ने किया है।

सर, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि कमजोर वर्ग पर एट्रोसिटीज़ रोकने के लिए एट्रोसिटीज़ एक्ट पास करके कई प्रावधान किए गए हैं, जिससे उनके ऊपर अत्याचार रुकेंगे। यहां हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के आदरणीय मंत्री बैठे हुए हैं। उन्होंने एक्ट में संशोधन करने का बिल पार्लियामेंट से पास कराया, ताकि दलितों के ऊपर एट्रोसिटीज़ का जो एक्ट है, उसमें खास और कड़े बंदोबस्त किए जा सकें और उनका परिपालन भी हो सके, ताकि उनके ऊपर अत्याचार न हो सकें।

महोदय, मैं दूसरी बात कहूंगा कि देश में कई राज्यपाल बनाए गए, लेकिन एससी वर्ग से कभी राज्यपाल नहीं बनाए गए, लेकिन इस सरकार ने पहली बार आदरणीय राम नाथ कोविंद जी को राज्यपाल के रूप में बिहार भेजा। इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी दलित को राज्यपाल बनाया गया।

महोदय, दूसरी अनेक बातें हैं, जिन्हें मैं बताऊंगा। 'मुद्रा बैंक' के माध्यम से गरीबों और छोटे उद्यमियों को 15 लाख रुपए ऋण के रूप में देने की व्यवस्था की गई है। ...(**व्यवधान**)...

श्री जयराम रमेशः सर, इससे पहले श्री जगन्नाथ पहाड़िया जी भी राज्यपाल रह चुके हैं।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): ठीक है। श्री शम्भुप्रसादजी, आप अपना भाषण जारी रखिए।

महंत शम्भुप्रसादजी तुंदियाः सर, मैं कहना चाहता हूं कि अभी नोटबन्दी का विषय चल रहा था। कैशलेस करेंसी की बातें हो रही हैं, तो उसमें भी 'भीम ऐप' के माध्यम से डा. बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम को पूरे देश की बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का प्रयत्न आदरणीय प्रधान मंत्री, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 'भारत इंटरफेस फॉर मनी' नाम की मोबाइल ऐप लॉच कराई गई है। ये बातें दलितों के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण बातें हैं, जो पहले कभी नहीं हुई थीं, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ये सब बातें देश में हो रही हैं।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष जी, माननीय पं. दीन दयाल जी उपाध्याय की जन्मशती वर्ष के उपलक्ष्य में इस वर्ष को 'गरीब कल्याण वर्ष' के रूप में मनाए जाने की घोषणा भी हुई है। हमारी पार्टी के स्थापक एवं वरिष्ठ नेता गण, जिन के विचारों में 'अन्त्योदय' की बात आई थी और उन्होंने 'अन्त्योदय', यानी जो समाज के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति के विकास के लिए काम करने के संकल्प के साथ काम करने की नींव रखी थी, आज उसे आदरणीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हम चरितार्थ होता हुआ देख रहे हैं।

महोदय, गरीबी उन्मूलन के लिए बहुत सी बातें यहां कही गईं। 26 करोड़ से अधिक लोगों के 'जन-धन' खाते खोलकर लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से पहली बार जोड़ा गया है और पहली बार अब कैशलेस व्यवस्था से गरीब लोग जुड़ रहे हैं। जिस गरीब ने कभी बैंक देखा नहीं था, जो कभी बैंक नहीं गया था, वह व्यक्ति आज कार्ड लेकर घूम रहा है। आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने तो एक साल पहले ही कह दिया था कि जन-धन के खाते खुलवाओ, ताकि यह हो सके।

महोदय, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि लोग किस प्रकार से सोच रहे हैं, लेकिन मैं समझ रहा हूं यदि कैशलेस व्यवस्था होगी, तो जिस छोटे मजदूर को 10,000 या 15,000 हजार रुपए की पगार पर रखा जाता है और उसे हकीकत में केवल 5000 रुपए देकर चलता कर देते थे, लेकिन अब कैशलेस व्यवस्था में उसके एकाउंट में फैक्ट्री वालों को उसका पूरा वेतन जमा कराना होगा। इस प्रकार उस गरीब को जो पगार मिलती है, वह बैंक टू बैंक जाएगी। उसमें कभी घपला नहीं होगा। हमने अनेक फैक्ट्रियों में ऐसा देखा है कि मजदूर को कैश में पूरा वेतन नहीं दिया जाता है और बाकी वेतन कंपनी के लोग खा जाते हैं। इस समय, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने जो कैशलेस की व्यवस्था की है, जिसमें एटीएम टू एटीएम, बैंक टू बैंक या खाते से खाते में कैश ट्रांसफर किया जाएगा, इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी और जो मजदूर, जो छोटे कर्म काम करते हैं, उन्हें उनका पूरा वेतन मिलने का अवसर प्राप्त होगा तो मैं यह कह रहा हूँ ...(**समय की घंटी**)... कि ये सभी जो बातें हैं, यहां पर प्रत्येक वक्ता ने कही हैं। आदरणीय शरद जी तो यह कह रहे थे कि दलितों का कहीं पर उल्लेख ही नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि 'उज्ज्वला योजना' दलित-पीड़ित महिलाओं के लिए है। 'जन-धन योजना', 'अटल पेंशन योजना' आदि किनके लिए हैं? ये सभी योजनाएँ उनके लिए हैं, जो छोटे लोग हैं, समाज के अंतिम छोर पर जो बैठे हुए व्यक्ति हैं।

[महंत शम्भुप्रसादजी तुंदिया]

अपनी बात खत्म करने से पहले, मैं अंत में एक बात बताना चाहता हूँ। मैं परसों भरूच जिले के एक गाँव में गया था। आदरणीय अहमद भाई अभी नहीं हैं। अगर वे होते, तो कहते कि वे उस गांव को पहचानते हैं। जम्बुसर तहसील का कावली नामक एक गांव है। वहां मैं गया था। मैं जैसे ही यहां से गया, तो पूरा गांव ऐसे उमड़ पड़ा जैसे कि मेरे स्वागत के लिए आया हो। वे मेरा स्वागत करने नहीं आए थे, वे तो आदरणीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करने के लिए आए थे। उनके मन में यह भावना थी। उस समय वहां भरूच जिले में उस भीड़ में मुस्लिम बिरादरी के भी कुछ लोग थे। मैं सही कह रहा हूँ। आप का नाम लिख लीजिए— 'कावली गांव, जम्बुसर तहसील, डिस्ट्रिक्ट— भरूच'। उसमें से एक मुस्लिम बिरादर ने आकर मुझे बताया कि पहली बार हमें यह महसूस हो रहा है कि किसी को हमारी चिन्ता है। पहली बार ऐसा लग रहा है और पहली बार ऐसा शान्ति का माहौल हमने 10-15 सालों में यहां पर देखा है। उसमें खुश होने की ही बात है, गौरव की बात है। उसने यह कहा कि ये अंधियारे गलियारे जो पड़े थे, वहां एक सूरज निकला है। एक सदी पहले, दो सदी पहले एक नरेंद्र नाम का सूर्य विलायत की भूमि पर जाकर, शिकागो की भूमि पर एक संदेश दे आया था, आज यहां एक दूसरा नरेंद्र निकला है, जो पूरा सूर्य उदित हो चुका है। उस मुस्लिम बिरादर ने नरेंद्र मोदी जी के लिए जो पंक्ति कही थी, उस पंक्ति को कह कर मैं अपनी बात खत्म करूँगा। उसने कहा किः—

"है अगर हिम्मत तो अंधेरे में आकर मिला करो,
धूप में तो कांच भी चमका करते हैं।"

उसने कहा कि इस अंधियारे गलियारे को उजियारा करने के लिए आपकी सरकार ने जो काम किए हैं, हम उसकी सराहना करते हैं।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष जी, आपने महामहिम जी के अभिभाषण पर बोलने का मुझे अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका और हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का धन्यवाद प्रकट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

SHRI NARENDRA KUMAR SWAIN (Odisha): Mr. Vice-Chairman, Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on the President's Address. There are a number of programmes like Jan Dhan Yojana and Deen Dayal Antyodaya Yojana mentioned in the Address of the hon. President. This has been circulated by the Centre to the States. First of all, I support the Motion of Thanks to the President's Address. The demonetization announced by the hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi has been supported by the entire people. They are happy because they live in villages. I know of my village wherein 50 per cent of people are daily wage workers. They earn their livelihood by working in the fields. They do not have land of their own. Much earlier, in the year 1982, land reforms were carried out there. So, small farmers have got land of only two acres by which they are earning their livelihood. I myself was a practising lawyer in the High Court. My family had only two acres of land.

4.00 P.M.

My family still have those two acres of land and my family earns its livelihood by cultivating paddy in this land. In my village, which is a very big village, 98 per cent of the people own just one or one-and-a-half acres of land. But there was no irrigation and people were living in great difficulties. The BJD Government, which has been in power for the last 17 years, has provided irrigation in the rural areas of the State. Sir, 11.5 per cent of land is irrigated, which I think is the highest percentage in the whole of India. In no other State has so much percentage of land been irrigated. However, a lot of problems have arisen due to other reasons including politics, which I would not touch. I would talk about them on some other occasion. Some other States, where the BJP has come to power, have created a lot of problems and they have tried to block the river waters. This has created a lot of problems. Odisha is one State where 11 per cent of the land is irrigated. Out of 30 districts, 22 districts have been given access to river water. Now, some obstacles have been created by the neighbouring States, but I don't wish to mention that while speaking on the Motion of Thanks to the President's Address. I will talk about them on some other platform. Anyway, I support all the programmes that have been mentioned here in the Address. I only hope that these would be implemented properly so that the people of our country are benefited. But, looking at the statements that have been made here, it seems poor people would not be easily benefited. This is only for publicity; it would be difficult to implement it. Friends from the BJP must work hard to implement these programmes in the rural areas, so that people living there will be benefited by these programmes. This booklet containing the President's Address that has been circulated to us is very useful. We support the entire programme that has been mentioned there. I hope this would help the poor and the downtrodden.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair*)

But the workers living in villages, those who are cultivating land, would not be benefited because they do not own a piece of land and because they are earning their livelihood only by working as labourers. So, whenever they are not able to go to the fields to work as labourers, they starve. I feel there is nothing in this programme for them. The hon. President's Address is silent on that issue. Ninety per cent of the people in the villages, especially those who work as labourers, virtually starve during the rainy season because they do not get any work and, hence, they do not have any food to eat.

However, I support what has been mentioned in the President's Address. I hope these programmes would be implemented by the Ruling Party.

With these words, I conclude my speech.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Now, Shri C. M. Ramesh, absent. Shri T. G. Venkatesh.

SHRI T. G. VENKATESH (Andhra Pradesh): Mr. Deputy Chairman, Sir, I thank you for giving me the opportunity to deliver my speech on the Motion of Thanks on the Address of the hon. President, Shri Pranab Mukherjee, on the eve of commencement of Budget Session of the Parliament on 31st January, 2017.

Sir, I feel, it is my privilege to express my opinion on the President's Address on behalf of the Telugu Desam Party.

The hon. President in his speech has given detailed programmes of this Government which have commenced after this Government came to power and which will be undertaken in the coming days for the development of the country.

The initiation taken by the Government on the LPG subsidy "giveit- up campaign" is marvellous and praise-worthy. Really, the subsidy foregone by the people has helped the poorest of the poor to get LPG connections.

The Swachh Bharat Abhiyan is also a great programme of the Government which motivated the people to go for cleanliness. It has inculcated health consciousness in the minds of people to a great extent. The popularity it has gained, is laudable.

Stopping of open defecation has also given good results and the people have assimilated the idea of the Government, and started construction of the toilets at their homes which has become true only with the financial support of the Government.

Further, Jan Dhan Yojana scheme introduced by the Government is also a great thing which has got a good momentum and led to opening of bank accounts by the unbanked people.

The hon. President has also said that his Government has started many social security programmes like Deen Dayal Antyodaya Yojana aimed at empowerment of women from the deprived sections, PM Aawas Yojana, which is to provide shelter to the houseless poor, with appropriate interest subvention, Pradhan Mantri Mudra Yojana aimed at providing collateral free bank loans for promotion of small business, issue of RuPay debit cards for promotion of cashless payments, Pradhan Mantri Ujjawala Yojana meant for providing cooking fuel, LPG for the poor SCs and STs, Deendayal Gram Jyoti Yojana to remove darkness in the houses of the poor, Ujala LED bulbs distribution Yojana, Mission Indra Dhanush which aimed at affordable healthcare, Direct Benefit Transfer LPG cash benefit scheme, Digi Dhan Abhiyan etc. have led the country to transform into a new society with the vision of this Government, is also praiseworthy. Lots of poor people have been benefited by these schemes.

Moreover, the hon. President has also said that the programmes undertaken by this Government for the welfare of kisans supplemented to increase the acreage yield of kharif and rabi crops, has also proven good for the development of the farmers. The other programmes *viz.*, e-NAM which assures good market and remunerative prices for the produce of the farmers, supplying seeds and fertilizers, improving irrigation facilities, through Soil Health Cards, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana aimed at risk coverage of the agricultural fields, Kisan Credit Cards meant to get access of credit through NABARD, Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana aimed at improving micro irrigation facilities, have also proven good for the welfare of the farmers. Large numbers of farmers are experiencing the benefits through these schemes and suicides graph of farmers is coming down.

In addition to the above, the hon. President has also detailed that the schemes launched for the benefit of the women in the country like *Nari Shakti* utilization, aimed at utilizing the skills and talents of the women by providing equal opportunities to them, *Beti Bachao Beti Padao* Scheme aimed at improving girl child's education, Suraksha Samriddhi Yojana aimed at securing the future of the girl child by depositing ₹ 11000 crores for them, Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan to provide comprehensive ante-natal care for pregnant women by qualified medical practitioners, revision of the Maternity Benefit Act to give more leave for pregnant ladies have also been widely spread, especially, among the rural women folk and they are getting the maximum benefits.

In the same way, opening of Skill Development Centres across the country, Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, National Apprenticeship Promotion Scheme, Pradhan Mantri Yuva Yojana, Stand-up-India, for the benefit of youth to improve their skills and employability, are increasing the skills of the young people. Hon. President has also informed that the bold decisions taken by the Government, like Demonetisation, implementation of OROP in the defence field, undertaking surgical strikes at borders, launch of BHIM Mobile Payment system, Aadhaar Payment System, streamlining of process of appointments, One-Nation-One-Tax system through GST, sustained global growth, liberalization of FDl Policy, facing terrorism, global affairs, global outreach, agreements with foreign countries for the development of India are leading our country into all-round sustainable development of the country.

I express profound thanks on behalf of my Telugu Desam Party to the hon. President of India for mentioning about all the developmental schemes and steps taken by this Government for bringing all-round development of the country. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Mr. Venkatesh. Mr. Biswajit Daimary is not present. Mr. Ram Vichar Netam, please.

श्री राम विचार नेताम (छत्तीसगढ़): माननीय उपसभापति महोदय, आज मेरे लिए यह सौभाग्य की बात है कि मुझे इस सदन में बोलने का मौका मिला। खासकर, महामहिम के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए मैं यहां उपस्थित होकर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

उपसभापति महोदय, यह सौभाग्य की बात है कि जो ऐतिहासिक अभिभाषण प्रस्तुत हुआ, उसके प्रथम उद्धरण में ही महामहिम ने जिन शब्दों का उल्लेख किया है, उसी से मैं ऐसा मानता हूँ कि देश के इतिहास में आज़ादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ कि समय से पूर्व एक साथ बजट प्रस्तुत हुआ। हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार का जो लेखा-जोखा है, उसको एक दस्तावेज के रूप में महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सदन में प्रस्तुत किया गया। सरकार ने लगातार पिछले दो सालों में इस देश के लिए, इस देश के विकास के लिए, इस देश की बेहतरी के लिए, इस देश के मान-सम्मान एवं स्वाभिमान के लिए जो कदम उठाए हैं, जो कार्यक्रम चलाए हैं, उन योजनाओं को महामहिम ने अपने अभिभाषण में बहुत ही अच्छे शब्दों में प्रस्तुत किया है। चेयर ने मुझे यहां बोलने की अनुमति दी, उसके लिए मैं माननीय सभापति जी, हमारे सदन के नेता और अपने दल के वरिष्ठ साथियों का निश्चित तौर पर आभार व्यक्त करता हूँ और उनका अभिनन्दन करता हूं।

[**उपसभाध्यक्ष (श्री तिरुची शिवा)** *पीठासीन हुए*]

उपसभाध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी, तो उससे पहले देश में एक ऐसा वातावरण था, जिसमें चारों तरफ निराशा की बातें थीं, देश निराशा में डूबा हुआ था और ऐसा कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था कि वास्तव में हमारे देश के मान-सम्मान और स्वाभिमान पर जो बट्टा लग रहा है, उसमें जो कमी आ रही है, उसमें शायद कहीं कुछ अच्छा हो। लेकिन इस निराशा से आशा की ओर बढ़ते हुए देश की जनता ने भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को माननीय नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करते हुए, उन्हें प्रधान मंत्री के रूप में निर्वाचित किया और लोकतंत्र के इस मंदिर में सर्वाधिक मतों से सबसे अधिक सांसद बना करके यहां बैठाया। उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने जिस कार्य संस्कृति का विकास किया, वह निश्चय ही काबिले तारीफ है। देश के इतिहास को बदलने का माद्दा रखते हुए उन्होंने जो कदम उठाए, निश्चित तौर पर आगे चल करके वे स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाएंगे। यही कारण है कि उन्होंने अपनी कार्य संस्कृति को जिस प्रकार से बढ़ाया कि "सब का साथ, सब का विकास" इन बातों को लेते हुए, सभी का सहयोग लेते हुए उन्होंने जिस समय शपथ ली, उस शपथ के माहौल में भी उस कार्यक्रम में तमाम पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुला कर के एक संदेश दिया कि हम पड़ोसी देशों से कैसा सम्पर्क करना चाहते हैं, कैसा संबंध स्थापित करना चाहते हैं। यही नहीं, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, चाहे किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ हो, सब को साथ लेकर के देश की बेहतरी के लिए उन्होंने जो खाका तैयार करके काम करना शुरू किया, उसमें चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या अन्य-अन्य पार्टी के हों, बिना भेदभाव के तमाम जितने भी हमारे अन्य-अन्य प्रदेशों के माननीय मुख्यमंत्रीगण हों, उन सब को शामिल करते हुए जिस प्रकार से देश के विकास के लिए संरचना करके जो काम करना शुरू किया, निश्चित तौर पर हम उन्हें बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कह रहा था कि आज यह अवसर हम सब को मिला है इस देश के नवनिर्माण करने का। उपसभाध्यक्ष महोदय, जिस समय इक्कीसवीं सदी की बात हो रही थी, उस समय अटल जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार थी। अटल और आडवाणी जी के

रूप में देश को नेतृत्व मिला हुआ था। तब के बाद जब 10 साल का जो कार्यकाल आया, उस 10 साल के कार्यकाल में सब को मालूम है कि हमारे देश की स्थिति क्या बनी थी, विदेशों में हमारी क्या छवि बन रही थी। उससे उभर करके देश की जनता ने जिस नेतृत्व को आज यह काम सौंपा है, निश्चित तौर पर हम यह कह सकते हैं कि आज देश की जनता गौरवान्वित है कि हमने ऐसे हाथों में नेतृत्व दिया है कि देश के विकास के लिए, देश की बेहतरी के लिए, देश के मान-सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए वे काम कर रहे हैं। आज विदेशों में इसी का डंका बज रहा है। उपसभाध्यक्ष महोदय, आज हम कह सकते हैं कि देश ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी आज पूरे विश्व के लोग यह मानने लगे हैं कि इक्कीसवीं सदी अगर कहीं है तो वह आज भारत में है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक ही बात पर हम नहीं कहना चाहते, बल्कि हम अगर जीडीपी की बात करें तो जहां 2012-13 में 5.6 प्रतिशत की जीडीपी हमारे देश की थी, आज हम यह कह सकते हैं 2015-16 में 7.6 प्रतिशत इतने कम समय में यह वृद्धि हुई है, यह छोटी-मोटी बात नहीं है। यही नहीं, हमारे तमाम वरिष्ठ लोग यहां हैं, इतने सारे विद्वानों के बीच में मैं ऐसे सुदूर अंचल से चल करके, अनुसूचित जनजाति वर्ग से आकर के आज इतने बड़े समुद्र में यहां बैठ करके आपके बीच में बात कर रहा हूं, तो यह साहस देने का भी अगर किसी ने काम किया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है कि मुझे उस गांव से लाकर के आज यहां यह अवसर प्रदान किया है। उपसभाध्यक्ष महोदय, आज यही नहीं, उन गांवों, गरीब किसानों की बात है। मैं इस अभिभाषण में देख रहा था कि अगर किसी के लिए योजना सबसे अधिक चली है तो वह गरीब के लिए चली है। आज गांव, गरीब, किसान, मज़दूर और नौजवान की चिन्ता करते हुए बजट में प्रावधान किया गया है और इस अभिभाषण में इन सबको शामिल किया गया है।

अगर हम Railway connectivity की बात करें, तो एक ज़माना था कि रेलवे में toilets नहीं हुआ करते थे। वहां रेलवे में डिब्बे की बात कर रहे हैं, उसमें सीट अरेंजमेंट नहीं होता था। इसी तरह से स्टेशनों की बुरी हालत थी। डिब्बों की हालत ऐसी थी कि उनमें चढ़कर दूसरी जगह जाना मुश्किल होता था, स्टेशन पर पहुंचकर वेटिंग रूम में बैठना मुश्किल होता था, लेकिन आज हम दावे के साथ यह कह सकते हैं, पूरा देश इस बात को देख रहा है कि आज स्टेशनों की हालत ऐसी है, जैसे फाइव स्टार होटल हो — ऐसी स्थिति बनी है। आज आप कहीं पर भी जाकर स्टेशन पर भोजन कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट कर सकते हैं — इतनी अच्छी व्यवस्था है। मैं समझता हूं कि यह जो क्रांतिकारी परिवर्तन आ रहा है, यह छोटी-मोटी बात नहीं है।

रेलवे कनेक्टिविटी के साथ-साथ, चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात करें या रोड कनेक्टिविटी की बात करें, सब जगह परिवर्तन आया है। आज चारों तरफ — उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक आप किसी भी राज्य में देख लें, चाहे आप पूर्वांचल में जाएं या पश्चिम में जो राज्य हैं, वहां जाएं, चाहे आप उत्तरांचल की बात करें या हिमाचल की बात करें या दक्षिण में केरल, कर्णाटक की बात करें, वहां पर जिस तरह से आज National Highways का काम चल रहा है, वह देखने लायक है। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह आपकी भी जानकारी में है कि आपके यहां कितनी बड़ी-बड़ी स्कीमों में काम हो रहा है। वह पहले क्यों नहीं हो रहा था? वह आज क्यों दिखायी दे रहा है? आज कनेक्टिविटी काफी बढ़ गयी है। आज लाखों-करोड़ों रुपए खर्च करके रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ायी जा रही है। 1 लाख 21 हज़ार करोड़ रुपए सेफ्टी प्वाइंट के लिए रखे गए हैं। ये सभी बातें हैं।

[श्री राम विचार नेताम]

यही नहीं, आज हमारा जो नेतृत्व है, इस नेतृत्व को देखकर देशवासी का सीना स्वाभिमान से चौड़ा हो जाता है। उसे लगता है कि कोई नेतृत्व है। आज विदेशों में जब हमारा नेतृत्व खड़ा होता है — चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो या अफ्रीका हो — किसी भी देश में जाकर जब हमारे प्रधान मंत्री बोलते हैं तो देश गौरवान्वित महसूस करता है, देश गौरवान्वित होकर देखता है कि हमारा कोई लीडर बोल रहा है। यही नहीं, जो तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जो हमारे पड़ोसी देश हैं — आप सबको इस बात पर गर्व होना चाहिए, हमें भी गर्व होता है कि दो मुस्लिम देशों ने, सऊदी अरब ने, जहां मक्का और मदीना हैं और उसके साथ-साथ अफगानिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष ने हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी को वहां के नागरिक का सर्वोच्च सम्मान दिया। यह छोटी-मोटी बात नहीं है। आज़ाद भारत में आज तक किसी भी प्रधान मंत्री को इतना बड़ा सम्मान नहीं मिला, लेकिन उन्हें आज यह सम्मान मिला।

उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने जो दस्तावेज प्रस्तुत किया है, महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण के रूप में सरकार के कामकाज का लेखा-जोखा एक तरह से यहां प्रस्तुत किया गया है। निश्चित तौर पर हमारी सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों से प्रेरणा लेकर काम करने वाली सरकार है, हम उनसे प्रेरणा लेकर काम करने वाले लोग हैं। जो अभिभाषण प्रस्तुत किया गया है, उसमें सरकार के विकास का जो खाका प्रस्तुत किया गया है, उसमें जो विकास कार्य दिया जा रहा है, वह सर्वस्पर्श है, सर्वग्रही है, सर्वसमावेशी है। इन विचारों को लेकर हम चल रहे हैं। ...(**समय की घंटी**)...

महोदय, बहुत सी बातें हैं। मैं कहना चाहता हूं कि चाहे राशन कार्ड की बात हो, चाहे राशन वितरण की बात हो, चाहे रेलवे कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे जन-धन योजना की बात हो, चाहे फसल बीमा योजना की बात हो, इन सभी योजनाओं में खास करके अगर किसी को केंद्र बिन्दु बनाया गया है तो गांव, गरीब, किसान और मज़दूर को बनाया गया है। इन्हें केंद्र बिन्दु बनाकर, गरीबों को केंद्र बिन्दु बनाकर हमारी सरकार का दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Please conclude.

श्री राम विचार नेतामः इसलिए मैं इसका समर्थन करते हुए महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और माननीय प्रधान मंत्री जी को तथा माननीय सदन को धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस अभिभाषण पर अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। सदन के तमाम सदस्यों ने मेरी बात को गंभीरता से सुना। यदि मुझसे बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करें, धन्यवाद।

श्री नरेंद्र बुढानिया (राजस्थान)ः उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं। मैं पिछले दो-तीन दिन से लगातार बहस को सुन रहा हूं। मैंने सभी वक्ताओं को ध्यान से सुना है और बहुत अच्छी बातें सामने आईं हैं। जब राष्ट्रपति जी के अभिभाषण प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद जी रख रहे थे, तो उन्होंने बहुत सी बातें बताईं। उन्होंने खास बात यह बताई कि देश बदल रहा है, इस देश में परिवर्तन हो रहा है। यह बात बड़े जोर-शोर से कही। उन्होंने इसके पक्ष में कहा कि हमारी सरकार अनेकों योजनाएं लेकर आई है, हमारी सरकार ने बहुत सी घोषणाएं की हैं, उन्होंने "मेक इन इंडिया" की बात कही, उन्होंने "स्टार्टअप

इंडिया" की बात कही, उन्होंने "स्टैंडअप इंडिया" की बात कही और अनेक योजनाएं गिनाईं। उन्होंने बहुत सी बातें सदन के सामने रखें। मैं पूछना चाहता हूं कि घोषणाओं की दुकानें तो आपने बहुत सी खोल लीं, लेकिन इन दुकानों में माल कितना बिका? यह तो आपको देश की जनता को बताना चाहिए। दुकान खोलने से कुछ नहीं होता है, माल कितना बिका, यह मैटर रखता है। यह देश की जनता आपसे जानना चाहती है। आपकी घोषणाएं तो बहुत अच्छी हैं। ये कागजों में बहुत अच्छी लग रही हैं। ये कम्प्यूटर में फीड हैं, इसलिए ये बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन जमीन पर उतरीं कि नहीं, यह देखने वाली बात है। मैं आज सरकार को बताना चाहता हूं कि आपकी घोषणाएं जमीन पर नहीं हैं। आपकी घोषणाएं कागज पर चल रही हैं। आपके पास समय है, आपका ढाई साल से ज्यादा का समय चला गया है, अभी आपके पास एक साल का समय बचा है, इस एक साल के समय में आप देश के लिए कुछ करना चाहें, तो करने की कोशिश कर लीजिए, अन्यथा यह एक साल का समय भी चला जाएगा, उसके बाद चुनाव का समय आ जाएगा। आपकी कोई सुनने वाला नहीं होगा। आप घोषणाएं करते जाइए, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। आपने महामहिम राष्ट्रपति जी से किसानों के बारे में कहलवाया है, आपने बार-बार कहा है कि आप किसान का कायाकल्प कर देंगे, आपने कहा कि हम किसान की आय को दोगुना कर देंगे। आज देश के किसानों को इन सब बातों पर हंसी आ रही है। आप सिर्फ किसान की बात करते हैं, लेकिन किसान के बारे में कुछ सोचा नहीं जाता है। आज हमारे देश के अंदर किसान की क्या हालत है। आज हमारा किसान ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आपने किसानों के लिए बहुत लम्बी-लम्बी बातें कही हैं। मैं आपको हकीकत बताना चाहता हूं, मैं किसानों के बीच में रहता हूं, मैं गरीबों के बीच में रहता हूं। मैं आपको उनकी हकीकत बताना चाहता हूं। आज किसान की क्या हालत है। यह सच है कि जब फसल बोने का समय आया, तो किसान के पास पैसा नहीं था। किसान की आंखों में आंसू थे कि वह बीज कहां से खरीदे, वह खाद कहां से खरीदे? आप कल्पना नहीं कर सकते कि किसान ने क्या-क्या नहीं किया, किसान ने कहां-कहां अपनी झोली नहीं फैलायी होगी, अपने खेत के लिए बीज प्राप्त करने के लिए, खाद प्राप्त करने के लिए! क्या सरकार किसानों को समय पर बीज उपलब्ध नहीं करा सकती थी? क्या खाद और कीटनाशक उपलब्ध नहीं करा सकती थी? लेकिन सिर्फ जुमले ही जुमले हैं। सर, मुझे एक गाना याद आता है, "वायदे पर तेरे मारा गया", लेकिन अब कहते हैं, "जुमले पर जुमला तेरा" और "तेरे जुमले पर मारा गया वह किसान और गरीब बेचारा।" आज आप के बारे में लोग यह सोच रहे हैं। सर, जब किसान की फसल तैयार हो गयी, तो क्या किया सरकार ने? सर, सरकार ने मुंह फेर लिया। किसान की फसल मंडियों में सड़ती रही, उसे कोई लेने वाला नहीं था। किसान की फसल बरसात में भीगती रही, उसे कोई देखने वाला नहीं था। तब किसान ने अपनी पैदावार को सड़कों पर फेंक दिया या फिर औने-पौने दामों पर उसे बेच दिया। आज हमारे देश के किसानों की यह हालत है।

सर, मैं एक किसान का बेटा होने के नाते सरकार से कहना चाहता हूं कि आपको देश ने चुनाव में इतनी सीटें दी हैं और इस में किसान का एक बड़ा रोल है। क्या आपको किसान को उसकी फसल का बोनस नहीं देना चाहिए था? आज किसान की चने की फसल चल रही है, जिसका बीज उसने 15 हजार रुपए क्विंटल के भाव से लिया है। आज उस का भाव 5 हजार रुपए क्विंटल पर आ गया है और जब उसकी पैदावार खेत से बाहर आएगी तो उसका भाव 3 हजार रुपए होगा और उसे कोई खरीदने वाला नहीं होगा। आप सोचिए क्या हालत है किसान की? मैं सरकार से मांग करता हूं कि कम-से-कम 20 प्रतिशत बोनस किसान को दिया जाए।

[श्री नरेंद्र बुढानिया]

यदि आप किसान के सच्चे हितैषी हैं और किसान की उन्नति चाहते हैं, आप किसान की ताकत बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको एमएसपी का रेट बढ़ाना होगा। अगर उसे उसकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिला तो देश का किसान बरबाद हो जाएगा, लोग खेती करना छोड़ देंगे और देश मंझधार में आ जाएगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि किसान की ताकत बढ़ाने के लिए एमएसपी का रेट बढ़ाया जाना चाहिए। आप नहीं मानेंगे, यह मुझे पता है, लेकिन मैं अपना मन तो हल्का कर लूं। मैं अपने किसानों को कह तो सकूं कि किसान भाइयो, मैंने सदन में आपकी बात ताकत के साथ रखी है।

आपने बातें बहुत की हैं। आपने पैदावार दोगुनी करने की बात की है। आप पैदावार कैसे बढ़ाएंगे? आपने सिंचाई की बात की, लेकिन सिंचाई के लिए आप क्या कर रहे हैं? सर, सिंचाई के लिए कोई योजना नहीं है। आज सिंचाई के पानी के जितने भी disputes हैं, वे सारे सालों-सालों से वैसे ही पड़े हैं। सर, मैं राजस्थान से चुनकर आता हूं। आज वहां का किसान बहुत तकलीफ में है। राजस्थान का किसान बहुत मेहनती है। वह आपकी तरफ देख रहा है। उसे पीने का पानी चाहिए, उसे पानी नहीं मिलता। वह सिंचाई के लिए पानी की उम्मीद रखता है, लेकिन वह उसे नहीं मिलता है।

सर, मैं अभी राजस्थान के चुरू जिले के एक गांव तारा नगर में गया। वहां कुछ किसान धरने पर बैठे थे और मैं उनसे मिलने गया। तो मुझे बताया गया कि वहां के किसान पानी की मांग पर तीन महीने से धरने पर हैं। यहां हमारे राजस्थान से मंत्री जी बैठे हैं, उन्हें यह बात मालूम है कि वहां के किसान आंदोलनरत हैं। वे पीने के पानी और अपनी जमीन की सिंचाई के लिए आंदोलन कर रहे हैं। उन किसानों ने मुझ से कहा कि आप जाकर देश के मुखिया को बताइए, आप केंद्र सरकार को बताइए कि हमें हमारे पानी के हक से क्यों रोका जा रहा है? सर, राजस्थान की सब से बड़ी कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल ने बाड़मेर और जैसलमेर जैसी जगहों को पानी दे दिया, उस कैनाल की 5 लिफ्ट कैनाल थीं, जिनके माध्यम से रेगिस्तान को पानी देने की योजना थी। वह योजना बनी और उसको कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान में बनाया, लेकिन आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि उन पांचों लिफ्ट कैनाल्स का आधा रकबा सिंचाई से वंचित कर दिया गया। मैं तारा नगर में जिस धरने पर गया था, उस आधे रकबे में सबसे ज्यादा हिस्सा वहां का कटा। आज आप किसान की बात करते हैं, तो फिर किसान आप से कैसे प्रभावित होगा? इसलिए मेरा निवेदन है कि इस देश की बड़ी आबादी किसान है और इस किसान के लिए आप कुछ करें, तो अच्छा होगा।

मैं आप से एक बात और कहना चाहता हूं कि देश को सम्बोधित करते हुए 30 दिसम्बर को जब प्रधान मंत्री जी मन की बात कर रहे थे, तो मैं आपको सच्ची और हकीकत बात कहना चाहता हूं कि उस दिन देश के सारे गरीब आदमी, इस देश के सारे मजदूर, इस देश के सारे कमजोर लोग, किसान, महिलाएं, वृद्ध, नौजवान और बच्चियां, सभी टी.वी. के सामने बैठे थे। उनके दिल में था कि आज देश के मुखिया और हमारे प्रधान मंत्री जी हमारे लिए कुछ बोलेंगे। प्रधान मंत्री जी ने देश से 50 दिन का समय मांगा था। 50 दिन पूरे होने के बाद जब वे देश को सम्बोधित करने के लिए टी.वी. पर आए ....(**समय की घंटी**)... तब पूरा देश हक्का-बक्का रह गया। उन्होंने अपने आपको प्रधान सेवक बताने के अलावा जनता के लिए कुछ भी नहीं बोला। उनका भाषण सुनकर जनता निराश हो गई। लोगों ने सोचा था कि किसान का कर्ज माफ होगा। हम सब लोग

भी आस लगाए बैठे थे कि आज प्रधान मंत्री जी गरीब आदमी के लिए कुछ बोलेंगे। हमने सोचा था कि आज वह असली वक्त आ गया है जब हमारे देश के प्रधान मंत्री किसान की बात करेंगे और किसान का ऋण माफ करेंगे। जब लोगों ने उनका भाषण सुना, तो मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता कि लोगों की कैसी हालत थी। आपको किसान के बारे में सोचना चाहिए और किसान का कर्ज माफ करना चाहिए। आपको किसान कभी बोलेगा नहीं। बड़े-बड़े लोग कर्ज लेते हैं, तो उनका कर्ज तो माफ भी हो जाता है और वे कर्ज लेकर भाग भी जाते हैं, लेकिन बेचारा किसान आपके लिए काम करता है।

मैं कुछ बातें नौजवानों के बारे में भी कहना चाहता हूं। जब सरकार 2014 में चुनाव जीतकर आई थी, तो आपने रोजगार की बात कही थी कि हम करोड़ों की संख्या में रोजगार प्रदान करेंगे। आज क्या हुआ, आपने नोटबंदी का तुगलकी फरमान जारी कर दिया और रोजगार देने के बजाए करोड़ों लोगों को बेरोजगार कर दिया, यह क्या बात हुई? क्या देश की जनता आप से यही अपेक्षा रखती है? क्या देश के नौजवान आप से यही अपेक्षा रखते हैं? जब आपने नोटबंदी की घोषणा की तब आपने कहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं। आपने कहा कि हम काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं। आपने कहा कि इस देश में नकली नोट आ रहे हैं, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। इस लड़ाई में पूरे देश ने आपका साथ दिया। आपका साथ गरीब ने दिया, किसान ने दिया, मजदूर ने साथ दिया, वृद्ध, महिला और नौजवान सबने आपका साथ दिया कि यदि आप आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, काले धन को बाहर निकालने के खिलाफ लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं, तो हम आपके साथ हैं। मुझे यह कहते हुए अपनी पार्टी पर और अपने नेताओं पर गर्व है कि उन्होंने यह बात कही, तो कांग्रेस ने कहा कि कांग्रेस हमेशा भ्रष्टाचार से लड़ती रही है, कांग्रेस हमेशा काले धन के खिलाफ लड़ती रही है और आतंकवाद से लड़ती रही है। यदि आपकी भी ऐसी मंशा है, तो हम आपके साथ हैं, लेकिन जब असलियत सामने आई ...(**समय की घंटी**)... तो आपका जितना पैसा छपा हुआ था, वह सारा छपा हुआ पैसा वापस बैंक में जमा हो गया। आज देश आपसे यह तो जानना चाहता है कि कितना काला धन आया? यह तो आपको देश को बताना पड़ेगा कि कितना काला धन आया? आपको यह इसलिए बताना पड़ेगा क्यों कि देश के गरीब लोगों की लाइन में, कतार में लगने से सौ से ज्यादा मौतें हो गईं। उन मौतों का कौन जिम्मेदार है? उनके परिवारों के प्रति आज कौन जिम्मेदार है? आपको बताना तो पड़ेगा कि जिन सौ लोगों ने अपनी आहुति दे दी, न सिर्फ हजारों लोगों ने इतनी तकलीफ़ें भुगतकर, लाइन में खड़े होकर इतनी यातनाएँ और तकलीफ़ें सहीं, उनके लिए आप वह बताओ तो सही! आपसे न तो काला धन आया, न आतंकवाद रुका, न ही भ्रष्टाचार की कोई बात सामने आई। सारा पैसा आ गया, इसलिए अब आप डिजिटल इंडिया की बात करने लगे, कैशलेस की बात करने लगे। मुझे बताइए कि क्या हिन्दुस्तान कैशलेस हो सकता है? हिन्दुस्तान कैशलेस नहीं हो सकता है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Thank you, Mr. Budania.

श्री नरेंद्र बुढानियाः सर, मुझे थोड़ा-सा, दो-तीन मिनट्स और बोलने दीजिए, मेरा आपसे यह निवेदन है। आपने नोटबंदी की, लेकिन क्या हमारे देश के अंदर यह संभव है? आपने जो कैशलेस की बात कही, क्या वह संभव है? मैं अभी तीन दिन पहले एक गरीब आदमी की शादी में गया था। हमारी परंपराएँ हैं। हमें वहां पर शगुन देना पड़ता है। हमें शगुन के तौर पर वर-वधू

[श्री नरेंद्र बुढानिया]

के हाथ में कुछ देना पड़ता है। क्या वे वहां पर देने के लिए मशीन लगाएंगे? आप सोचिए तो सही। स्मृति ज़ूबिन इरानी जी, आप बैठी हैं, आप जानती हैं कि जब आप शादी में जाती हैं, तो लिफाफा देकर आती हैं। आप लिफाफा देती हैं। ...(**व्यवधान**)... हम अब क्या देंगे? हम शगुन के लिए क्या देंगे? आपके ये कार्ड कहां तक चलेंगे? मैं गडकरी जी से क्या पूछूँ? जब पूछूँगा तो उनसे पूछूँगा कि यदि कुछ हुआ है, तो आपको मुझे भी बताना पड़ेगा।

उपसभापति जी, मैं बोलना तो नहीं चाहता था, चूँकि यह बात सामने आ गई, जब हमारे सम्माननीय सदस्य ने यह बात कही, तो मैं इसको समझ रहा था।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे बेटे की शादी थी। उसकी 16 जनवरी की शादी तय थी। मैं 11 नवंबर को संबंध करने गया। 11 नवंबर की तारीख तय थी और 8 तारीख को नोटबंदी का तुगलकी फ़रमान जारी हो गया। जब नोटबंदी का फ़रमान जारी हो गया और जब वहां पर संबंध करने गये, तो शगुन का पैसा किसी के पास नहीं था। मेरे संबंधी की आँखों में आँसू थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि आज का तो हो जाएगा, लेकिन शादी कैसे होगी? इसलिए आप इसको आगे खिसका दीजिए। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं इस देश को बताऊँ कि ऐसे लोग भी हैं। मैंने उनसे कहा कि नहीं, 16 तारीख को शादी नहीं होगी, हम अभी, इसी वक्त शादी करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे पास माला ही नहीं है। हमने कहा सूत की माला डाल दीजिए। सूत की माला से शादी हो गई। सूत की माला से शादी हो जाती है, लेकिन तकलीफ़ तब होती है, जब आपके मंत्री करोड़ों रुपये की शादी कर रहे होते हैं। जिस दिन शादी पचास-पचास रुपये में हुई, उसी दिन 500 करोड़ रुपये में भी शादी हुई। ये 500 करोड़ रुपये कहां से आए? मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं? उसी दिन हमारे केंद्रीय मंत्री के बेटे की शादी थी। उस शादी में करोड़ों-करोड़ रुपये खर्च हुए। सैकड़ों स्पेशल फ्लाइट्स गईं, हेलिकॉप्टर्स गए। यह पैसा कहां से आया? यह डबलिंग चलने वाली नहीं है। ...(**व्यवधान**)... यह डबलिंग चलने वाली नहीं है। मैं कहना चाहता हूं ...(**व्यवधान**)... मैं वास्तव में कहना चाहता हूं ...(**व्यवधान**)... गरीब की ...(**व्यवधान**)... आपने जोर-शोर से सर्जिकल स्ट्राइक की बात की। जब आप सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Thank you, Mr. Budania. ...(*Interruptions*)... He is speaking well, but I have given double the time that was allotted

श्री नरेंद्र बुढानियाः उपसभापति जी, मैं बहुत कम बोलता हूं, मैं आपसे थोड़ी-सी बात और कह दूं। ...(**व्यवधान**)... सर, सरकार कहती है कि हम गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। रवि शंकर प्रसाद जी ने सर्जिकल स्ट्राइक और नोटबंदी के बारे में बड़े जोर-शोर से बात कही, हमारे माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी से भी कहलवाई और आज प्रधान मंत्री जी जब उधर बोल रहे थे तो इसके बारे में बहुत जोरदार तारीफ कर रहे थे। मैं यह कहना चाहता हूँ कि आपने जो सर्जिकल स्ट्राइक की बात कही, अच्छी बात है, हमारे देश के जवानों पर हमें गर्व है, हमारी फौज पर हमें गर्व है, लेकिन आज सर्जिकल स्ट्राइक करने की आवश्यकता किस चीज पर है? आज गरीबी के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करने की जरूरत है, आज बेरोजगारी के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करने की जरूरत है। अगर आज इनके खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की गई, तो न

तो हमारे किसान हमें बख्शने वाले होंगे, न देश के नौजवान हमें बख्शने वाले होंगे और न ही गरीब हमें बख्शने वाले होंगे। कोई हमें बख्शने वाला नहीं होगा।

उपसभाध्यक्ष महोदय, समय किसी का इंतजार नहीं करता। आगे समय आने वाला है। यह प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र के अंदर पांच साल के बाद हिसाब देना होता है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): You have too many papers. Time allotted to you is nine minutes. I have given twenty minutes. You are speaking very well, but please conclude.

श्री नरेंद्र बुढानियाः सर, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि एक लंबे समय से मैं यह बात सुन रहा हूँ कि आजादी के बाद इन 70 सालों में इस देश में कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, तो क्या ढाई साल में सब कुछ हो गया? क्या देश पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को भूल सकता है?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Thank you, Mr. Budania. Please conclude.

श्री नरेंद्र बुढानियाः क्या यह देश इन्दिरा गांधी जी को भूल सकता है? क्या यह देश राजीव गांधी जी को भूल सकता है? आज इस देश में जितने बड़े-बड़े कारखाने हैं, जितने बड़े-बड़े पी.एस. यूज़ हैं, उन्हें इस देश में स्थापित करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। आज उन पी.एस. यूज़ में करोड़ों-करोड़ लोग काम कर रहे हैं, उन्हें रोजगार मिला हुआ है। यह उनकी परिकल्पना थी। इन्दिरा जी ने नारा दिया था कि लोग मुझे हटाना चाहते हैं और मैं गरीबी हटाना चाहती हूँ, तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Brevity is the soul of wit. Thank you very much.

श्री नरेंद्र बुढानियाः किसानों की उन्होंने पीठ थपथपाई। किसानों से कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी और "हरित क्रांति" लेकर आईं। आज हमारा देश अपने पैरों पर खड़ा है। आप सब कुछ आज यह भूल गए। हमारे इतने मिसाइल परीक्षण हुए हैं, इतने परमाणु परीक्षण हुए हैं, "चंद्रयान", "मंगलयान", आज हम कहां पहुंचे हैं? क्या यह सब ढाई साल के अंदर हो गया?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Mr. Budania, See, your party has some other Members. They will also participate.

श्री नरेंद्र बुढानियाः देश की जनता समझती है कि इस देश की आजादी कांग्रेस पार्टी ने करवाई, इस देश का जनतंत्र कांग्रेस पार्टी ने बचाए रखा। जो इस देश के अंदर एक संविधान की स्थापना हुई, जिसकी रक्षक कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार बनी...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Thank you, Budaniaji.

श्री नरेंद्र बुढानियाः लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे अल्पसंख्यक मंत्री यहां नहीं हैं, चले गए हैं, पूछना चाहता हूँ कि आपने दलित के लिए क्या किया? आपने अल्पसंख्यक के लिए क्या किया? आपने महिला सशक्तिकरण की जो बात कही, उसके लिए आपने क्या किया? बातें तो आपने बहुत बड़ी बनाई हैं, लेकिन हमारे यहां दिल्ली में आज महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, आज

[श्री नरेंद्र बुढानिया]

दूसरे देश के पर्यटक हमारे देश में आना नहीं चाहते हैं। यहां पर कोई सुरक्षित नहीं है। दिल्ली में तो आपकी पुलिस है। यदि आपकी पुलिस है, तो कम से कम इस दिल्ली में तो सुरक्षा का कुछ करिए। हम लोग कहीं जाते हैं, तो वहां लोग हमें शर्मिदा करने की कोशिश करते हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इन सब बातों के साथ एक निवेदन करना चाहता हूँ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Thank you, Budaniaji.

श्री नरेंद्र बुढानियाः मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी समय है और समय रहते हुए आप चेत जाइए। आप सिर्फ ब्रांडिंग मत करिए, सुधर जाइए और गरीब, किसान, नौजवान, महिला के लिए जो वायदे आपने किए हैं, उन्हें जमीन पर लेकर आइए। मैं यही बात करना चाहता हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद।

DR. NARENDRA JADHAV (Nominated): Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir, for the opportunity to participate in the discussion. At the very outset, I wish to compliment the hon. President for very comprehensive and insightful Address outlining policy priorities of the Government.

Sir, by the end of March, 2017, the Twelfth Five Year Plan will come to an end. This will not only be the end of the Twelfth Five Year Plan but it would be an end of an era of over six decades of planning in India. What is the future of planning process in India? There is a talk about a long-term perspective plan but there is no clarity about the future of planning process in India. I wish the hon. President had elaborated on this critical issue, which has a bearing on the future of the Indian economy and Indian society.

The second issue that I want to raise is an implementation issue. Reportedly, a very large amount of allocation for scholarships for Scheduled Caste and Scheduled Tribe students has not been spent, and the amount is as large as a few thousand crores of rupees. Sir, this is a grave situation which merits immediate and urgent attention.

The third issue that I want to point out is the abolishment of Scheduled Caste sub-Plan and the Tribal sub-Plan. As you are aware, the Scheduled Caste sub-Plan and the Tribal sub-Plan were established in 1979 and 1975 respectively linking the allocation for the empowerment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in proportion to their shares in the population at the national level as well as at the State level. Regrettably, there is now an abolishment of the Scheduled Caste sub-Plan and the Tribal sub-Plan and they have been replaced by general schemes like 'Allocation for welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes'. Instead, there should be a transparent, accountable, efficient and effective Centrally-sponsored scheme, an umbrella scheme, for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, which will continue to link Scheduled Castes and Scheduled Tribes allocations to their respective shares in population.

Sir, much has been said about demonetization. I have supported demonetization from day one. I am convinced that demonetization entails short-term pain and medium to long-term gains. What has happened, Sir, is that the short-term pain has been exaggerated while the long-term gains have been under-played. Serious objections have been taken, I am not going into all of them but I want to point out two or three of them. One of the very serious objections which have been taken is that money has been taken away from the poor people. Actually, what has happened or what is happening is exactly to the contrary. What is actually happening is the re-distribution of wealth from the tax-evading wealthy and corrupt people to the poor people of our country. This is a Robin Hood kind of a job which the Hon. Prime Minister is doing, for which we need to compliment the Prime Minister rather than criticizing him. ...(*Interruptions*)... I come to the second point. ...(*Interruptions*)... There is an argument made... ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Please continue. ...(*Interruptions*)...

DR. NARENDRA JADHAV: The second point that I want to make about demonetization is that there is a lot of talk that the total amount of fake currency in our country is only ₹ 400 crores. It is being said that if the total amount is only ₹ 400 crores and the ratio of fake currency to the total currency is only 0.02 per cent, which is very small, why should we demonetize very large amount of currency, which is more than ₹ 14.5 lakh crore? Sir, this is a very insensitive kind of an argument because what is being done is to make a strike against the counterfeit currency, which has been financing the terrorism in our country.

How many people have died due to terrorism in our country? Sir, from 1993 to 2016, the total number of deaths due to terrorism has been something like 35,000. Now, if somebody makes an argument about the ratio of the terrorism-related deaths of 35,000 to the total Indian population of 125 crore, saying that this ratio is incredibly small, does that mean that the terrorism problem is a small problem? So, what is being done is to make a strike, and a very right kind of decision has been taken to make a strike at the fake currency issue.

The third objection that has been raised is that enough preparation was ...(*Interruptions*)... Sir, who is running this House? Is the Chair running this House or somebody who is sitting there?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): You please continue. ...(*Interruptions*)...

DR. NARENDRA JADHAV: Thank you, Sir.

There is also an argument made that enough preparation was not made for

[Dr. Narendra Jadhav]

demonetization, and particularly the issue of recalibration of ATMs has been raised. Sir, I know a thing or two about this because I worked with the Reserve Bank of India all my life, for thirty-one years, and I was involved in this process. In ATMs, there were three bins — hundred rupees, five hundred rupees and one thousand rupees bin. And they are highly sensitive to the weight and size. Now, if the Government or the Reserve Bank of India had issued instructions to all the commercial banks that you recalibrate all your ATM machines with the new size of hundred, five hundred and two thousand rupee notes, it would have obviously leaked out what was the intention of the Government. So, it means that on one hand the Government had to go on preparations and, at the same time, on the other hand, secrecy had to be maintained. I think the timing of demonetization was perfect, striking the right kind of balance between the adequate preparations to be done on one hand and maintaining the secrecy of this event on the other hand. So, it is fully justified.

The fourth point that I want to make about demonetization is that a lot of people believe that a very large amount of money more than fourteen lakh crores has come back to the public sector banks and private sector banks. Some people see that as a failure of the scheme. It is exactly the opposite. The money which was lying around, the cash hoardings which were kept in the secret places, stored in ceilings, in the floors and places like that, all that money has come back into the formal system. This is an achievement. This is a big step in financial inclusion. Also, the criticism is made that the money coming back to the banking system means that the black money, which was there earlier, has now become white money. Again, to the contrary, because the investigation is on where if the money which has been credited to the accounts, deposited to the bank accounts is disproportionately larger than the known sources of income of the depositors, the investigation is going to reveal that. Why the total amount of black money has not been revealed is because this investigation is going to take some time. Even in the 31st December speech of the hon. Prime Minister, people said that the total figure was not disclosed. Even in case of data like prices data, inflation data, GDP data, there is always a lag between the happening and the release of the data. It will require certain amount of time before the data is clearly available about how much black money has come back into the system. Sir, all in all, a lot of people have predicted that this is going to hurt our economy very badly. In fact, the former Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, on the floor of the House said that the GDP will come down by two percentage points and it will take a long time to recover. You know, all the estimates now show that the actual decline in GDP rate of growth is going to take place only in the third and fourth quarters of the current financial year, and would be less than one percentage point for the financial year as a whole and from the year beginning 1st April, 2017, the

5.00 P.M.

new financial year, not only the growth rate will come back to the earlier levels, but there will also be an acceleration of growth with creation of lot of jobs. So, this is demonetization completely changing the way Indian economy has been functioning, has been operating. It is going to make it more transparent, more accountable, more clean and, therefore, more sustainable growth in future.

Sir, I thank you for your indulgence and also for giving me the opportunity to speak. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Thank you very much. Now, Mr. Biswajit Daimary - not present; Mr. Ramdas Athawale - not present. Mr. Abdul Wahab.

SHRI ABDUL WAHAB (Kerala): Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak. I know that I could get this chance because a lot of Members are absent.

The President's Address came at the right time. It was delivered on 31st January, the day after the martyrdom of Mahatma Gandhiji, who was killed by some criminal. The 30th of January is the anniversary of his martyrdom. On 31st January, my leader, the tallest among the parliamentarians, E. Ahamed *sahib*, died on the floor of the Central Hall of Parliament. It was a very sad day for me. The next day, on *Basant Panchami*, the Government of India presented the Budget.

In the President's Address, everything was very clear. He was narrating what they have given him to narrate. It included all the programmes which were introduced by our hon. Prime Minister Narendra Modiji. Everything was explained. My only regret is that after demonetisation whatever money came back to the exchequer or the RBI is not known till today.

I remember the election of George Bush Junior. In Florida, there was some confusion in counting of votes. The election result was delayed for many days. It seems Americans can't count more than ten. It took them around seventy-eight days to recount the votes and to tell it to the Supreme Court. We are talking about Digital India. Dr. Narendra was talking about RBI. According to me, 16,000 employees are employed by our RBI. It may be a little here or there. In this digital age, our RBI could not give the details of the exact amount which came to it whether it is black money or terror money or this money or whatever money. Till today, this amount is not known to the public. Even we don't know about that. It is still a secret. It will take some time. The data may be coming late. It may take its own time. Even the RBI does not know what is happening. I want to say one more thing about the President's Address.

[Shri Abdul Wahab]

A lot of money is given for agricultural sector. It is good. I appreciate that. But how are they going to disburse this money through NABARD? My concern is about Kerala. The cooperative banks are not functioning because of RBI's rules. My request to them, through you, Sir, is this. Just activate the cooperative banks, so that whatever money is there, it reaches the needy farmers. Maybe the RBI may not be agreeing to this. It may say that whatever it decides is final. Though they know the mistake, they are not ready to accept that. The same thing happened with demonetisation. Hon. Prime Minister may not agree with this. But even his colleagues agree that demonetisation did not happen according to their vision or wish or what they had expected. My simple request is this. Leave the ego, just do the needful, at least, for the farmers.

The third thing, which I want to suggest, is that you change the name of Dr. Ram Manohar Lohia Hospital. You change it, according to your wish. Whichever the Government is, let them change the name of Dr. Ram Manohar Lohia Hospital. Dr. Ram Manohar Lohia was a socialist; he was a very good man. But, please see what is happening in Dr. Ram Manohar Lohia Hospital today. I have requested my kids also not to send me to Dr. Ram Manohar Lohia Hospital if at all something happens to me. ...(*Interruptions*)... I am staying nearby Dr. Ram Manohar Lohia Hospital. I am diabetic and a heart patient. If something happens, they will take me there. I am worried about that. Please send me to some other private hospital or if it is under your control, send me to AIIMS.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Why?

SHRI ABDUL WAHAB: I have seen what happens there. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Why did you mention the name of Dr. RML Hospital?

SHRI ABDUL WAHAB: Do you want me to explain that? ...(*Interruptions*)... On 31st January, after the President's Address, somebody told me that my leader expired and was sent to Dr. RML Hospital. So, I asked what 'my leader' means. He was a Parliamentarian. What is 'my MP'! I went there with Rahulji; Mr. Jyotiraditya Scindia was also there. I was there after that. From 12.15 p.m. to 2.15 in the night, I was there in Dr. RML Hospital seeing what they were doing with Ahamed Saheb. I am very sorry to say that. Doctors are supposed to work according to medical ethics. It is supposed to be 20 to 30 minutes of CPR with hands or machine. They are supposed to do that. But, it was happening for one hour to oneand-a-half hours. After somebody came, things changed. I am referring to it as 'body'. But, according to hospital, patient was shifted to another ICU and, then to Trauma ICU. Nobody

could see him; his kids could not see him. His daughter is a doctor. She is a pathologist; she is a professor in a medical university in UAE. His son-in-law is a nephrologist; he is a consultant in Dubai. They could not see the patient. According to me, it was a 'body'. Soniaji came; Rahulji came; Mr. Ghulam Nabi Azad, Mr. Ahmed Patel and a lot of people came. We were there. Mr. E.T. Mohammed Basheer, a lot of other people and Kerala MPs came. But, we could not see him. They did not allow us. Bouncers were there. Then, at last, we went to police station. We lodged a complaint. Police came and told them that these people should be allowed to see him. At that point of time, they agreed. We could only see Ahamed Saheb without any equipment on his body and he was dead. So, this is what I have seen. So, I don't want to go there. I am sincerely saying that please do not send me to Dr. RML Hospital and also, do not send any of our Members, including MPs from the Government side, to Dr. RML Hospital. That is why, I was explaining that. I don't want to talk about it more because it is about my leader. I cannot speak more. So, I am not going into that. I don't want to reopen that case. ...(*Interruptions*)... I don't want to reopen that because it is very emotional to me.

SHRI BHUBANESWAR KALITA (Assam): Sir, please direct the Minister to note it down. ...(*Interruptions*)...

SHRI ABDUL WAHAB: Sir, an earthquake was felt yesterday. I don't know whether you remember or not. I was near Dr. RML Hospital. My flat is nearby. It is Swarna Jayanti Deluxe. I am staying very close to Dr. RML Hospital. There were tremors. I thought they were from God to do something with Dr. RML Hospital, but it was not. I was standing there and looking at Dr. RML Hospital. I did not go out. My friend, Mr. Suresh Gopi, and all others went outside the flat. They were waiting there and I was standing there only. After 30 minutes, earthquake had gone. So, I thought yesterday that I may have to go to Dr. RML Hospital again.

Anyway, then, I come to the other things in the President's Address. My request is, whatever our President has said...

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MUKHTAR ABBAS NAQVI): One minute, please. ...(*Interruptions*)... He is yielding. ...(*Interruptions*)...

SHRI VAYALAR RAVI (Kerala): It is a very emotional issue. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Please, he is the Minister of Parliamentary Affairs. ...(*Interruptions*)...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वीः सर, इससे बहुत confusion create होगा, इसलिए वहाब साहब ने जो बात कही है... ई. अहमद साहब का इंतकाल हुआ है, उनके प्रति जितना दुख वहाब साहब को है, उससे ज्यादा दुख हम सबको है, क्योंकि वे एक पार्टी के लीडर ही नहीं थे, बल्कि वे एक बहुत अच्छे पार्लियामेंटेरियन थे और बहुत अच्छे नेता थे। डा. राम मनोहर लोहिया के बारे में सब लोग जानते हैं, वे इस देश के एक बहुत बड़े लीडर रहे हैं और देश के लिए उनके योगदान को कोई नकार नहीं सकता है। ...(**व्यवधान**)... इसलिए उनके नाम को बदल दिया जाए, यह मैं उचित नहीं समझता हूँ।

जहां तक आरएमएल हॉस्पिटल ने किस तरह से उनका ट्रीटमेंट किया, इसका सवाल है, उसके बारे में आरएमएल हॉस्पिटल ने प्रेस के माध्यम से और अपनी रिपोर्ट के माध्यम से बहुत डिटेल में कहा है। उसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। वहां पर उन डॉक्टर्स ने ई. अहमद साहब की देखभाल की, जो पहले भी उनकी देखभाल करते रहे हैं, क्योंकि यह फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है। इससे पहले भी उनका heart failure हुआ था, उस समय भी उन्हीं डॉक्टर्स ने उनकी देखभाल की थी और वे ठीक हुए थे। ...(**व्यवधान**)... हम सब चाहते थे कि वे ठीक हों, लेकिन unfortunately इस तरह की जो दुखद घटना हुई है, उसको लेकर किसी भी तरह से पूरे के पूरे अस्पताल पर आरोप लगाने या किसी डॉक्टर पर आरोप लगाने से इसका मैसेज ठीक नहीं जाएगा। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Please, please. ...(*Interruptions*)... Let him speak. ...(*Interruptions*)...

SHRI VAYALAR RAVI: Sir, it is a very emotional matter. ...(*Interruptions*)...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वीः अस्पताल में जो डॉक्टर्स हैं, उनमें से बहुत से अच्छे डॉक्टर्स हैं। ...(**व्यवधान**)... बहुत अच्छी ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर्स हैं। ...(**व्यवधान**)... सबके सब खराब हैं, ऐसा मानना ठीक नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Thank you. ...(*Interruptions*)... No, no. ...(*Interruptions*)... Please. ...(*Interruptions*)...

SHRI K. K. RAGESH (Kerala): Sir, ...(*Interruptions*)...

SHRI BHUBANESWAR KALITA: An hon. Member, with all sincerity and honesty, is saying something on the floor of the House. Do you want to say that he is telling the untruth and doctors are the only people who speak the truth? ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): No, no. ...(*Interruptions*)...

SHRI K. K. RAGESH: Sir, ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): No, no. ...(*Interruptions*)... Excuse me. ...(*Interruptions*)... Please. ...(*Interruptions*)... Mr. Ragesh, please sit down. ...(*Interruptions*)... Please sit down. ...(*Interruptions*)...

SHRI K. K. RAGESH: He was also a.....(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Kindly please sit down. ...(*Interruptions*)... Mr. Ragesh, please sit down. ...(*Interruptions*)... Mr. Abdul Wahab,..... (*Interruptions*)... No, no. ...(*Interruptions*)...

SHRI ABDUL WAHAB: Sir, I am not complaining. I am not blaming the Government or the Home Minister. I am not blaming but I can give one more..... (*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): You expressed your views and the Parliamentary Affairs Minister has given his explanation. Kindly resume with next part of your speech. ...(*Interruptions*)...

SHRI VAYALAR RAVI: No, no. ...(*Interruptions*)... It is not that simple. ...(*Interruptions*)... I am very sorry to say it is not that simple because Shri E. Ahamed was a tall leader of the Party. He was from Kerala. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): No; that can be on a separate motion. ...(*Interruptions*)... Not now. ...(*Interruptions*)... When he has raised something and an explanation has been given by the Minister. ...(*Interruptions*)...

SHRI ABDUL WAHAB: Let me complete. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Kindly continue. ...(*Interruptions*)...

SHRI ABDUL WAHAB: Sir, there is one more incident I want to explain and I will stop. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): No; you come to the President's Address, please. ...(*Interruptions*)...

SHRI ABDUL WAHAB: Yes, Sir. I called up our Chairman. Being a Member of Rajya Sabha, I contacted our hon. Chairman, Ansari Saheb, at around 10.30-11.00 and I asked for his help for his body to be shown to his kids. That is the justice. I told him, "I agree whatever has happened, but why were the doctors not allowing his son, daughter and daughter-in-law, who are all doctors, to enter?" But our Chairman told me, "Okay, Mr. Abdul Wahab. I will give you a call." He gave me a call and then I asked him. He told me, "After 12 o'clock you can call me. My telephone will be there with me up to 12 o'clock." Around 11.48 or 11.50, I called him again and told him, they are not allowing his kids to see the body, whether he is alive or not, but they are not agreeing." Mr. Naqvi, that is what happened. That was not supposed to happen in any hospital. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Kindly make a note of it. ...(*Interruptions*)...

SHRI ABDUL WAHAB: That he may do so, please. We are giving a submission to the hon. Prime Minister. Day after tomorrow, he has given time to submit our request. Please make an inquiry. We require an inquiry of a Parliamentary panel, if at all it is possible. Please do that. Thank you very much for giving me time and to Naqvi Saheb for explaining all. Thank you.

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री प्रकाश जावडेकर): मंचासीन उपसभाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी के बहुत ही अच्छे अभिभाषण पर यहां दो दिनों से चर्चा चल रही है और उसमें मैं दो-तीन बातों का जिक्र करना चाहता हूँ। मोदी सरकार आने के बाद, हमारी सरकार बनने के बाद फर्क क्या आया? ...(**व्यवधान**)... इसे समझने की जरूरत है। इस दौरान दो फर्क आए। ...(**व्यवधान**)... इस सरकार के सत्ता में आने के बाद क्या-क्या बदलाव हुए, उसकी एक तस्वीर राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में दिखाई है। हम सबको मालूम है कि दो खबरें हम पहले हमेशा पढ़ते थे। एक खबर पढ़ते थे कि देश में कोयले की किल्लत है, बिजलीघर कभी भी बंद हो सकता है। ऐसी खबर हर साल आती थी। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Prakashji, please address the Chair.

श्री प्रकाश जावडेकर: मेरे पास डिटेल्स हैं। ...(**व्यवधान**)... ऐसी खबर आपके राज में हर साल आती थी, क्योंकि उनके पास केवल एक दिन का या दो दिन का कोयला शेष होता था, you have coal stock for one day or two days. You were always reading the news that there is a danger that if the coal supply does not come, then, you have to stop production. Every State has seen that. This news has disappeared since the last two years. Why? We have not done any rocket science but it is because we gave the rate for coal transport without corruption and increased the coal supply and there is no corruption in the supply of coal. हमने एक कदम से भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया, जिससे देश का बड़ा संकट समाप्त हो गया और आपको यह चित्र मिलने लगा कि जहां एक तरफ कोयले का उत्पादन बढ़ा, वहीं उसका यातायात भी सुचारू हो गया और अब हर पावर स्टेशन पर 21 दिनों का कोयला, जो mandatory होता है, 21 दिनों की कोल-सप्लाई है। यह दर्शाता है — this is good governance. This is one of the items of good governance. ऐसा बदलाव इस क्षेत्र में आया। ..(**व्यवधान**)..

दूसरी न्यूज़ आप हर साल पहले सुनते थे कि यूरिया की किल्लत है। किसानों का आंदोलन होता था, उन पर लाठीचार्ज भी होता था। ...(**व्यवधान**)... नहीं हो रहा है। ...(**व्यवधान**)... नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने कोई ...(**व्यवधान**)... It is the intention that makes the difference in governance. Like this *neem* coating is not the science which we discovered. ...(*Interruptions*)... That is what I am saying. The scientists have discovered this much earlier. वह पहले ही तैयार था, लेकिन नीयत नहीं थी, तो नीम-लेपन नहीं हुआ। ...(**व्यवधान**)... नहीं हुआ। It was only 20 per cent before. अब यह 100 परसेंट हो गया। आप देखिए कि नीम कोटिंग से क्या हुआ। आप देख रहे हैं कि — Now, farmers require 10 per cent less fertilizers and get 10 per cent more crop. At the same time, with this neem coating,

the black market of subsidized urea which used to get diverted to chemical factories or other factories has stopped completely because now they cannot use urea as a pure nitrogen because nitrogen releases slowly. So, that is the trick. And, therefore, what has happened is that the whole corruption and scam in urea has gone away. These are just two news items which I am showing to display कि किस तरह से सरकार की नीयत में बदलाव होते ही good governance आई।

अब मैं demonitization पर आता हूं। Demonitization पर बहुत लोग बोले और मुझे भी अच्छा लगा। पहले लोगों को एक ही शिकायत रहती थी कि लोग कतार में लगे हुए हैं लेकिन अब कोई कतार नहीं है। ...(**व्यवधान**)... There is no queue. ...(*Interruptions*)...

SHRI SHANTARAM NAIK (Goa): Lakhs of people got unemployed. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Please. Shantaramji, please don't interrupt. ...(*Interruptions*)...

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: One minute. ...(*Interruptions*)... I am coming to that. मैं वही बता रहा हूँ, बैठिए। ...(**व्यवधान**)... Demonetization में पहले एक ही शिकायत थी कि कतार है, कतार है, कतार है, लेकिन अब तो कतार नहीं है। 50 दिनों के बाद, there is no queue. ...(**व्यवधान**)... वह क्यों नहीं है, इसलिए ये परेशान हो गए। यह कौन बोल रहा है? आपने दूध के लिए 50 साल कतार लगवाई, आपने राशन के लिए 50 साल कतार लगवाई, आपने गैस के लिए 50 साल कतार लगवाई, तब कांग्रेस का नाम ही queue था। तब पूरी जनता को, देश को हर चीज़ की किल्लत थी और उन सबको आपने queues में खड़ा करवा दिया था। अब 50 दिन के queue के लिए क्या आप आरोप लगाएँगे? आपने देश को 50 साल तक हर तरह की queue में खड़ा किया। ...(**व्यवधान**)... तब सामान नहीं मिल रहा था। ...(**व्यवधान**)... आप सुनिए, तब हमें दूध लेने के लिए भी कतार लगानी पड़ती थी। तब हर चीज़ के लिए कतार लगानी पड़ती थी। ...(**व्यवधान**)... अटल जी के समय ...(**व्यवधान**)... हर चीज़ के लिए देश को कतार में खड़ा करने वाले, जिन्होंने देश को 50 साल कतार में खड़ा किया, वे 50 दिन की कतार के लिए बोल रहे थे, यह सुनकर मुझे आश्चर्य हो रहा था। ...(**व्यवधान**)... चूंकि मीडिया वालों को भी न्यूज़ चाहिए, इसलिए वे भी कतारों में जाकर लोगों से पूछ रहे थे, लेकिन एक भी बन्दा उल्टा नहीं बोल रहा था, तो बड़ी दिक्कत थी। एक दिन ऐसा हुआ कि एक बड़े टीवी चैनल के एक बड़े पत्रकार जब एक queue में गए, तभी उस queue में खड़ा एक आदमी बेहोश हो गया। यह देखकर उनको लगा कि अब तो जबर्दस्त न्यूज़ मिल गई। लोगों ने उस आदमी के चेहरे पर पानी मारा, तो वह ठीक हो गया और उसको शक्कर वगैरह खाने को दी गई, तो वह एकदम खड़ा हो गया। फिर तुरंत उसके सामने माइक लगा दिया गया और उससे पूछा जाने लगा कि आप बेहोश हो गए, आपको तकलीफ हुई, इस पर आपका क्या कहना है? उस पर वह आदमी बोला कि नहीं, नहीं, मैं तो डायिबटीज का पेशेंट हूँ, आज मैंने दवा ली लेकिन शुगर नहीं खाई, इसलिए मैं बेहोश हो गया। उसने आगे कहा- मैं कतार में खड़ा हूँ, लेकिन मोदी जी ने जो किया, वह देश के अच्छे के लिए किया, हमारी भावी पीढ़ी के लिए अच्छा किया। यह वह बोल रहा था। The man, who was standing in the queue and got fainted, was also talking good about that. ...(*Interruptions*)... और यही मैं बता रहा हूँ। ...(**व्यवधान**)...

श्री शान्ताराम नायकः वे 100 लोग कैसे मारे गए? ...(**व्यवधान**)...

श्री प्रकाश जावडेकरः अभी आप सुनिए। ...(**व्यवधान**)... एक मिनट, अभी आप सुनिए। ...(**व्यवधान**)... आपके जमाने में तो इतने मरे, उसकी कोई गिनती नहीं है। वह आप छोड़ो। ...(**व्यवधान**)... मेरे मित्र, डी. राजा जी, मैं यह नहीं समझ रहा हूँ कि आप किसका समर्थन कर रहे हैं? ...(**व्यवधान**)...

SHRI DIGVIJAYA SINGH (Madhya Pradesh): Sir, I have a point of order. Is there a shortage of Members of Parliament in Rajya Sabha from BJP that the Minister has to intervene?

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: No; I am a Member of the House.

SHRI DIGVIJAYA SINGH: But you are a Minister.

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: But I am a Member of the House.

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Is there a shortage amongst the Members of Parliament? ...(*Interruptions*)...

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: No, no. But I am a Member of the House. I have given my name. ...(*Interruptions*)...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: He should be here not to... ...(*Interruptions*)...

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: I am a Member of the House. ...(*Interruptions*)... I have given my name. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): He is not intervening. He is... ...(*Interruptions*)...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Can he name one power plant... ...(*Interruptions*)...

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: This is no point of order. I am a Member of the House. ...(*Interruptions*)...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Can he name one power plant which was closed down because of lack of coal? ...(*Interruptions*)... Not one power plant. Give us a name. Give us an instance. ...(*Interruptions*)...

श्री बसावाराज पाटिल (कर्णाटक)ः आपको क्यों तकलीफ हो रही है? ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Digvijaya Singhji, please sit down. ...(*Interruptions*)... Rapolu*ji*, please don't interrupt.

श्री प्रकाश जावडेकरः इस demonetization में सबसे बड़ा आश्चर्य मुझे यह देखकर हुआ कि हमारे कम्युनिस्ट मित्र, डी. राजा जी किसके साथ खड़े हो गए? आप किसके साथ खड़े हो गए? जिनको छुपाना था, वे तो दुखी थे और जिनको छुपाना था, वे तो इसका विरोध करेंगे ही,

लेकिन जिसके लिए गरीब कह रहा है कि यह अच्छा कदम है, उसका विरोध करने के लिए आप खड़े हो गए! यह देखकर मुझे ताज्जुब हुआ। यह कैसे हो गया? कम्युनिस्ट्स पूरी जिन्दगी गरीब की बात करते रहे, मजदूर की बात करते रहे और आज कम्युनिस्ट्स एकदम उल्टी दिशा में जाकर उधर खड़े हो गए! यह देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। ...(**व्यवधान**)...

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Sir, because the Minister has taken my name, I must ask the Minister to speak on the unprecedented hardships, sufferings and humiliations which the people have to go through because of the demonetization policy. That is number one. Number two, he is MHRD. He must speak on education; he must speak about as to what is happening in Central Universities. ...(*Interruptions*)...

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: I am speaking. ...(*Interruptions*)...

SHRI D. RAJA: Instead of that, he is speaking on several other topics. ...(*Interruptions*)...

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: I am coming to that and there also, I will expose all of you. Please bear with me.

श्री प्रकाश जावडेकरः तो ये किस का समर्थन कर रहे थे? भ्रष्टाचार का कोई समर्थन करे, कर चोरी करने वाले का समर्थन करे, यह देश ने कभी नहीं देखा। इसमें पोलिटिकली एक पार्टी थी कि जिसको गरीब मानते थे कि यह हमारी पार्टी है। एक पार्टी गरीब के समर्थन का और "गरीबी हटाओ" का नारा दे रही थी। आज गरीब उनसे हट गया, गरीब का प्लान उनके पैरों तले निकल गया और वे हमारे पास आ गए। यह भी नहीं समझ रहे, वे किस का साथ दे रहे हैं? भ्रष्टाचार का साथ देकर गरीब आपके पास कभी नहीं रहेंगे। Therefore, the plank of the poor has gone. Now, let me come to two more points because I do not want to take more time. मैं दो बातों का उदाहरण देता हूं। मैं पर्यावरण मंत्री था। बॉर्डर सिक्यॉरिटी फोर्स की सबसे बड़ी दिक्कत थी बॉर्डर रोड्स की — 6,000 KMs of roads. The projects like Sea-bird Navy's ambitious project, many other Defence projects, Missile Ranges were all held up for years together, for 7 or 10 years, between 2004 and 2014. Why? I do not know for what bargain? So, Defence projects were not cleared. When I took charge, I discussed the matter with Defence forces ...(*Interruptions*)...

SHRI JAIRAM RAMESH: It is factually incorrect. I can give you information that 7,000 KMs of border roads proposed by the Army and the ITBP were all cleared. The former Defence Minister is not here. I can give you evidence. If he can prove that all roads of the Defence Department were not cleared between 2004 and 2014, I am prepared for a privilege motion.

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: I am saying this ...(*Interruptions*)... Don't threaten me. I have many records. The year is very clear. The Sea-bird project of the Navy at Karvar which was a very important project for the defence of the country was languishing for want of permission for four years. More than 6,000 KMs of border roads ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Mr. Palvai Govardhan Reddy, please sit down. ...(*Interruptions*)... Mr. Rapolu, please sit down. Let him speak.

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Border roads, Defence infrastructure and even the Coast Guard Police Chowki require CRZ permission which was not coming forth easily. Files were pending. What did we do? The difference is we discussed the whole problem with the Defence Ministry. My hon. friend, Mr. Rangarajan and our Members were there in the Defence Committee, and I was also part of the Standing Committee on Defence, and we gave general approval for all the Defence infrastructure, Defence Road projects within 100 KMs of Line of Actual Control. We took one decision to permit Defence infrastructure projects for the security of the country.

यह हमने करके दिखाया। So, that is the difference. उस समय डिफेंस मिनिस्टर जेटली जी थे। तब हमने डिफेंस सेक्रेटरी को फोन पर कहा कि इसका कुछ quid pro quo है। उसके बदले में हमें कुछ चाहिए। उन्होंने कहा कि क्या चाहिए? मैंने कहा कि hundreds of cities में डिफेंस की बहुत सारी लैंड है। उस लैंड के कारण रोड वाइडनिंग रूकी है, रेलवे ओवर ब्रिजेज़ रूके हैं, कहीं फ्लाई ओवर रूके हैं। 200 अरबन कार्पोरेशन सिटीज़ में जहां-जहां डिफेंस की लैंड के कारण जो सिविल एमिनिटीज़ के काम रूके हैं, तो हमने अगर आपके 200 प्रोजेक्ट्स एक झटके में मंजूर किए हैं तो आप भी ये अरबन डेवलपमेंट के लिए रोड्स के, फ्लाईओवर के और रेलवे ओवरब्रिज के जो प्रोजेक्ट्स आपके कारण पैंडिंग हैं, वे भी आप मंजूर करिए। ऐसा हमने bargain किया। सर, देश हित में bargain ऐसे होता है। देश हित में दूसरा bargain यह किया कि 9 वाट का LED bulb 300 रुपए का था। उसका दाम 300 रुपए से 75 रुपए कैसे हो गया? हमने कुछ नहीं किया। हमने दुनिया के और देश के सारे उत्पादकों को इकट्ठा बिठाया और उनसे मीटिंग की। हमने कहा कि हम 1 बिलियन bulbs का ऑर्डर देंगे, आप बताइए कि कितना प्राइस कम करेंगे? We asked them. पहले भी bargain होता था, अब हमारा bargain अलग है, उस समय का bargain अलग था — यह फर्क है। Bargain उस समय भी होता था, bargain हमारे समय में भी हुआ, हमारे समय में पब्लिक के interest में हुआ और 300 रुपए का बल्ब 75 रुपए में हो गया — यह बदलाव हुआ, यह मोदी सरकार का करिश्मा है, यह पारदर्शिता का एक मायना है। सीपीआई मानती है कि वह मज़दूरों की लड़ाई लड़ती है। मैं भी मंत्री बनने से पहले दो यूनियनों का अध्यक्ष रहा था। 42 per cent increase in wages in a single stroke! एक ही निर्णय में 42 per cent increase in minimum wages is a landmark and historical decision. We must appreciate that. This is the decision. 42 प्रतिशत minimum wages को increase किया। सिक्योरिटी गार्ड और बाकी छोटे-छोटे काम करने वालों के लिए मज़दूरी बहुत कम होती थी। आज उस मज़दूरी में इतनी बढ़ोतरी हो गयी है। अभी जो Ordinance हमारे पास आया है, जो अभी हमने पास किया है, उसमें मज़दूर को cheque से पैसा देने का provision है, ताकि उसको 100 परसेंट पैसा मिल सके। अगर कैश में पैसा देंगे तो कितना मिलेगा, उसका पता नहीं होता है — साइन कितने पर लिया और पैसे हाथ में कितने दिए, यह पता नहीं होता है। अब cheque से उसे पैसा दिया जाएगा, तो पता चलेगा कि कितना पैसा खाते में जमा हुआ है — यह transparency हम ला रहे हैं। आज मज़दूरों को एक Unique ID Number मिला है।

इससे उसकी नौकरी कहीं से कहीं भी बदले, उसका पता लग सकता है। मज़दूरों की मेहनत के जो दस-बारह हज़ार करोड़ रुपए लावारिस पड़े हुए थे और मज़दूरों का पता नहीं चल रहा था कि वे कहां हैं, उनके हज़ारों करोड़ रुपए पीएफ खातों में पड़े थे, वे सारे अब indentify होते जा रहे हैं, क्योंकि Unique ID Number मिल रहा है। These are simple but very important steps which show the change in the style of governance. यह style of governance कभी कांग्रेस का जनता के हित में नहीं रहा, गरीब की बात की और गरीब को लात मारी, यही सच्चाई है और हमने इसे बदला है। इसलिए गांव, गरीब, किसान, जवान, नौजवान — जब उनको न्याय दे रहे हैं, तब यह बात आयी। ...(**समय की घंटी**)...

सर, आखिर में मैं दो मिनट में एक बात और कहना चाहता हूं। हर साल लोगों को "पद्मश्री" मिलता है। अच्छा है, समाज में गुणी लोग हैं, मिलना चाहिए — पहले भी मिलता था, आज भी मिल रहा है - लेकिन इस बार कुछ विशेष हुआ। आज "पद्मश्री" भी ऐसे लोगों को मिला — जलपाईगुड़ी के चाय बागान में काम करने वाले एक मज़दूर को भी मिला, जो अपनी मोटर साइकिल से लोगों को ambulance की सेवा मुहैया कराता था। इसके लिए उसे "पद्मश्री" मिला। ऐसे गरीबों को ढूंढ़-ढूंढ़कर "पद्मश्री" दिया गया। यह कभी नहीं सोचा था कि किसी गरीब को ऐसा पुरस्कार मिलेगा, लेकिन इस बार ऐसा हुआ। मैं इसके लिए सारे मीडिया को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उस सूची में 15-20 ऐसे लोग हैं, जिनका नाम देश में लोगों ने पहली बार सुना, लेकिन वे अपने-अपने इलाके में सालों से जनता की सेवा अपनी commitment से कर रहे हैं — कोई पढ़ाई का काम करता है, कोई पेड़ लगाने का काम करता है, कोई बांध बनाने का काम करता है, कोई जल संवर्धन का काम करता है। ऐसे लोगों की सूची कभी किसी ने नहीं देखी थी, ऐसे लोगों को ढूंढ़ने का काम केवल प्रधान मत्री नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं — यह हमने देखा और इसलिए "पद्मश्री" की सूची भी बदल गयी।

सर, मेरा डिपार्टमेंट एचआरडी मिनिस्ट्री है। पहले स्मृति बहन वहां पर थीं। क्या आपको मालूम है कि उसमें कितने बदलाव आए? अभी शायद कल Zero Hour में एक मुद्दा उठाया गया था। उसमें कहा गया कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में छात्राओं पर कोई प्रतिबंध लगाया गया है। कोई प्रतिबंध नहीं है। मैंने आज वहां पूछा, मैंने वहां पर कुलपति से बात की तो उन्होंने कहा कि उसमें कोई बदलाव नहीं है, कोई नया नियम नहीं है, किसी के खाने पर कोई पाबंदी नहीं है, जो जिसको चाहिए, Food is a personal choice और इसके लिए किसी पर कोई बंधन नहीं लगाया गया है। वहां हॉस्टल में जो 8,000 छात्राएं रहती हैं, हमें गर्व है, वहां पर 14,000 छात्र रहते हैं, हमें गर्व है कि सबसे बड़ा रेजिडेंशियल कॉम्पलेक्स बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में है और वह अच्छा चल रहा है, लेकिन सभी विश्वविद्यालयों में, हमारे आने से नहीं, हमारे आने से पहले, आपके समय भी और आपके पहले के समय में ...(**समय की घंटी**)... यह नियम था कि 9 बजे के बाद अगर कोई भी लड़का या लड़की कहीं जाते हैं, तो वे वॉर्डन को बता कर जाते हैं कि कहां जा रहे हैं और कब आ रहे हैं, ताकि किसी को चिंता न हो। इसके बारे में पूछते हैं और यह नियम पहले से चल रहा है। वे बेवजह हमें ठोक रहे हैं, क्योंकि असत्य बोलो, लेकिन जोर से बोलो, यह एक नियम सा अभी चल रहा है, यह बदनाम करने का एक षड्यंत्र है, बाकी कुछ नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Please conclude.

SHRI ANAND SHARMA: Sir, he is a Minister. Let him speak…(*Interruptions*)…

श्री प्रकाश जावडेकरः और इसलिए ...(**व्यवधान**)...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, he is a Minister. Let him speak…(*Interruptions*)… He is a Minister. Let him speak now. There is a wedding in his family. He has to express himself.

श्री प्रकाश जावडेकरः इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनता बराबर समझती है, जनता ठीक समझती है कि क्या फर्क हुआ है? लोगों ने फर्क देखा है एक ईमानदार सरकार होना, एक पारदर्शी सरकार होना और प्रक्रियाओं में छोटे-छोटे बदलाव करते हैं, जैसे DBT के एक कारण, अगर साल में 50 हजार करोड़ रुपये बचते हैं, तो यह देश का बहुत बड़ा फायदा है, गरीब के साथ न्याय है, लूट करने वालों को सजा है। आप किसके साथ खड़े हो, लूट करने वालों के? मेरी अपील है, यहां भी बहुत अच्छे लोग हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि राजनीति में सभी तरह के लोग हैं, Politics is the most misunderstood and underrated profession. But, let us understand that we must remain with the honest; we must commit ourselves to the glory of the nation, to the real progress of the poor और उसको कुछ मिले। "सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा" यह नारा लेकर हम जा रहे हैं। यह लेकर ही हम काम कर रहे हैं और इसलिए मुझे लगता है कि हर मंत्रालय अगर अपना-अपना रिपोर्ट पेश करता है, ऐसा सेशन भी होना चाहिए। यह मध्यावधि एक तरह से एक रिव्यू है और राष्ट्रपति जी ने जो अभिभाषण दिया है, इसमें दोनों सरकारों की रीति-नीति और नीयत और नीति में क्या फर्क है, यह दिखा दिया है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Shri Ripun Bora.

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामदास अठावले): आनन्द शर्मा जी, आप प्राइम मिनिस्टर से पहले बोलने वाले हैं?

श्री आनन्द शर्माः पता नहीं। आप अपना बोलिए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Shri Ripun Bora. ...(*Interruptions*)... No, no. It comes as per the order. Mr. Ramdas Athawale, when you were called, you were not present. Now, your turn will come later. Now, Mr. Ripun Bora.

SHRI RIPUN BORA (Assam): Thank you, Sir, for giving me this opportunity. Many of the friends from the Treasury Benches, and even Dr. Narendra Jadhav, have highly complimented the President's Address. But, I do not find anything to be complimented there. There is no reason to express our thanks to the President of India for his speech because in this speech, there is nothing. All tall claims are there in the speech. But, according to the ground reality, there is nothing. This is not the speech of the President of India. Rather, it can be said as a speech of the BJP party only. I will come to the reply of Mr. Prakash Javadekar also as to what he has said about fifty years and fifty days. I will come to you after some time.

But, let me start with para 12. In para 12 of the President's Address, a mention has been made about Swachh Bharat Abhiyan, and that day, when the hon. Minister, Shri Ravi Shankar Prasad, while initiating the discussion, praised the Prime Minister very highly for taking jharu. सर, स्वच्छ भारत अभियान में चारों ओर झाड़ू लेकर सफाई की है। सर, प्राइम मिनिस्टर को झाड़ू लेकर सिर्फ दो मिनट सफाई करते हुए टी.वी. पर दिखाने से देश की सफाई नहीं होती है। सर, सफाई तो दिल से होनी चाहिए, लेकिन आप लोगों के दिल में क्या सफाई है? When we, the Opposition, say anything wrong about the Government, then we become anti-national, and when we point out the demerits of demonetization, we are lebelled by the Prime Minister himself that we are the protectors of black money! क्या यही है दिल से सफाई का नमूना? Sir, not only that; in the President's Address, it was mentioned that three crores of toilets have been constructed all over the country. I don't know where they have been built; but, I am mentioning, for record, the example of Assam. If it is wrong, I appeal you to form a Parliamentary Committee and let it visit Assam to find out new toilets. No toilets have been constructed. Whatever they claim, they are all half-done; not even half-done, just one-foot or two-feet is constructed and then left as it is, not to speak of the water connection.

Yesterday also, somebody said that toilets were constructed but there was no water. But, in Assam, not to speak of water connection in toilets, the construction is only half-a-foot or two feet and it is left there. The Gandhi Spectacles, which you use as the logo for Swachh Bharat Abhiyan, Gandhiji never wanted to see the display of his spectacles in this type of Swachh Bharat Abhiyan.

Sir, about demonetization, today I have got a reply from the hon. Finance Minister. The Prime Minister had said that the demonetization would completely wipe out the black money from our country. I am reading out from the reply of the Finance Minister: "These actions led to seizure of valuables of more than ₹ 610 crores, which include cash of ₹ 513 crores." Then, he says, "The undisclosed income detected in these actions, as on 10th January from 9th November, is ₹ 5,400 crores." Sir, as you see from these figures, where is the black money? When Enforcement Directorate officials and Income-Tax officials raided, they found illegal money of only ₹ 610 crores! Only ₹ 610 crores and the undisclosed amount they got is only ₹ 5,400 crores! India is a large country. According to the RBI, the total circulated money in ₹ 1,000 and ₹ 500 denomination notes was ₹ 16 lakh crores. This does not include the denomination notes of ₹ 100 or ₹ 50 or ₹ 20 or ₹ 10. Out of these ₹ 16 lakh crores, only ₹ 610 crores have been discovered as illegal money! So, where is the black money?

In the President's Address, it is very surprising to note that nowhere it is mentioned that 135 innocent persons died while they were in queue waiting for

[Shri Ripun Bora]
their hard-earned money. My question is: How did these people die? These people stood in the queue and they died not because of their fault. They went there and made a queue, to comply with the order of the Prime Minister. It is very surprising to note that neither the BJP Government nor the Prime Minister nor the President in his Address, has mentioned anywhere the sympathy for the people who died. No condolence, no commitment of any compensation to them is mentioned. How disgraceful it is!

Sir, let me come to para 14. In this, it is mentioned, "Under Deen Dayal Upadhayay Gram Jyoti Yojana, out of over 18,000 villages which had been in darkness since independence, 11,000 villages have been electrified.'' This is very shocking, Sir. In our State Assam, whatever villages we have electrified under Rajiv Gandhi Gram Vidyutikaran Scheme, it is lying there. Not a single pole, not a single post, not a single line has been electrified under Deen Dayal Gram Jyoti Yojana. That is why I am saying that the President's Address is only in book, only in black and white, not on the ground.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair*)

Apart from that, the President has highly spoken about the schemes of BJP Government — Digital India, Make in India, Start-up India, Get-up India, Stand-up India, Skill India and Smart Cities. Now my question is, Sir, why these names are in English. Why can't they be made in Hindi? The poor people, the common people, a daily wage earner, carpenter, cobbler, washer-man, barber, farmer, rickshaw-puller and others, they cannot pronounce the word 'Make in India', they cannot pronounce the word 'Digital India', they don't know what is the meaning of this, they don't know यह खाने का है या पहनने का है, उसको यह मालूम नहीं है। They have nothing to do with these schemes. These people know about food. They want security, they want pulses, they want drinking water, they want electricity and they want rice at ₹ 2 per kg. that our UPA Government had introduced. But nowhere in the Address of the President...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your party time is over. Please conclude. ...(*Interruptions*)... Time is over. Time is over.

SHRI RIPUN BORA: Nowhere in the President's Address there is any scheme for the common people, poor people. ...(*Interruptions*)... There is no scheme for alleviation of poverty. One more thing, Sir, it has been said that demonetization will curb terrorist activities. I am giving you one example, Sir. On Republic Day, on 26th January, ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ...(*Interruptions*)... Your party time is over. No, no. ...(*Interruptions*)...

SHRI RIPUN BORA: There was a series of bomb blasts. ...(*Interruptions*)... I want to draw the attention of the House to a very important issue. I want to draw the attention to an incident of 26th January. ...(*Interruptions*)... What happened in Assam is that there was a series of bomb blasts at eight places one by one. Secondly, the BJP State President of Assam in his office hoisted the National Flag upside down. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, okay. ...(*Interruptions*)... All right. ...(*Interruptions*)...

SHRI RIPUN BORA: This is disrespect to the nation.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Ramdas Athawale. ...(*Interruptions*)... It is over. ...(*Interruptions*)... Please sit down. ...(*Interruptions*)...

SHRI RIPUN BORA: I am completing. ...(*Interruptions*)...

MR DEPUTY CHAIRMAN: Nothing is going on record. ...(*Interruptions*)...

SHRI RIPUN BORA: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Nothing is going on record. ...(*Interruptions*)... Mr. Athawale is to speak and we are left with only ten minutes. ...(*Interruptions*)... Mr. Athawale, you take five minutes. Then Mr. Anand Sharma will start. At 6.00 p.m., we have to adjourn. ...(*Interruptions*)...

SHRI RIPUN BORA: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What Mr. Athawale speaks only that will go on record. ...(*Interruptions*)...

श्री रामदास अठावले: डिप्टी चेयरमैन सर, मैं अपनी पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। **...(व्यवधान)...** मैं कहना चाहता हूं कि **....(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have already taken twenty minutes. ...(*Interruptions*)... How can I do that? ...(*Interruptions*)... It is not going on record. ...(*Interruptions*)... Please don't disturb.

SHRI RIPUN BORA: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is not going on record. How can I do that? ...(*Interruptions*)... It is not going on record.

---

*Not recorded.

SHRI RIPUN BORA: *

श्री रामदास अठावलेः डिप्टी चेयरमैन सर, मैं यहां अपनी पार्टी की तरफ से खड़ा हुआ हूं। ...(**व्यवधान**)... मैं इतना ही कहना चाहता हूं। ...(**व्यवधान**)... बैठिए, बैठिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः बोलिए, बोलिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री रामदास अठावलेः क्या बोलूं? ...(**व्यवधान**)... जरा ठहरिए? ...(**व्यवधान**)... इतना क्यों तड़प रहे हैं? ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please don't disturb. ...(*Interruptions*)... It is not going on record. ...(*Interruptions*)... Please sit down. Anand Sharmaji, ask him to sit down. ...(*Interruptions*)... Please sit down, Shri Ripun Bora.

SHRI RIPUN BORA: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down. It is not going on record.

श्री रामदास अठावलेः इनको जरा बोलिए। ...(**व्यवधान**)... कांग्रेस वाले इतना क्यों तड़प रहे हैं? ...(**व्यवधान**)... कांग्रेस वाले इतना क्यों तड़प रहे हैं? आपको सरकार का समर्थन करना चाहिए। ...(**व्यवधान**)... आनन्द शर्मा जी, इनको बोलिए ...(**व्यवधान**)... इनको बिठाइए। ...(**व्यवधान**)... बिठाओ, बिठाओ। ...(**व्यवधान**)... आनन्द शर्मा जी, आपका टाइम खत्म हो जाएगा।

सर, इनकी जो भावना है, ये लोग मन से इतना तड़प रहे हैं कि हमारी सरकार आ गई। ...(**व्यवधान**)... मैं उधर था। ...(**व्यवधान**)... मुझे इधर आना पड़ा। ...(**व्यवधान**)... क्यों आना पड़ा? आपके मन में यह जो भावना है ...(**व्यवधान**)... एक तो कांग्रेस पार्टी ऐसी है ...(**व्यवधान**)... लोकतंत्र को मानना चाहिए। अगर हमें बहुमत मिला है, नरेंद्र मोदी जी को बहुमत मिला है, तो उनका समर्थन करने की आपकी जिम्मेदारी है। ...(**व्यवधान**)... मैं बताना चाहता हूं किः—

महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में ...(**व्यवधान**)...
महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में होती है सरकार की दिशा
नरेंद्र मोदी जी को है विकास का नशा।
गरीबों को है सरकार से न्याय की आशा
क्योंकि मोदी सरकार रोज नहीं बदलती है अपनी भाषा।
सारे देश में आ गई है नरेंद्र मोदी जी की आंधी
इसलिए परेशान दिख रहे हैं तुम्हारे राहुल गांधी।
नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के लिए की है नोटबंदी
आप क्यों कर रहे हो राजनीति गंदी।
काला धन करने वालों की टूटने वाली है फांदी
लेकिन हमारे जैसे लोगों की होने वाली है चांदी। ...(**व्यवधान**)...
सबका विकास-सबका साथ

*Not recorded.

हमारी सरकार का नारा है — सबका विकास, सबका साथ
नरेंद्र मोदी जी हमेशा करते हैं मन की बात।
नरेंद्र मोदी जी हमेशा करते हैं मन की बात
वे चाहते हैं मजबूत करना है गरीबों का हाथ।
वे चाहते हैं मजबूत करना है गरीबों का हाथ
इसलिए सभी दे रहे हैं, मोदी जी का साथ। ..(**व्यवधान**)..

आप क्यों नहीं दे रहे हैं? लोकतंत्र में जिस तरह बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संविधान दिया है, जिसको बहुमत मिलता है, सरकार यहां जो भी काम कर रही है, उस सरकार का समर्थन करने की जिम्मेदारी अपोजिशन की होती है। वहां अभी तुम्हारी मेजोरिटी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद, पांच राज्यों के चुनावों के बाद उधर हमारी मेजोरिटी हो जाएगी। हम कानून बनाएंगे। हम आपके फायदे के कानून बनाएंगे, सबके फायदे के कानून बनाएंगे, देश के फायदे के कानून बनाएंगे, लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि आप लोग मन में इतना क्यों तड़प रहे है? ...(**व्यवधान**)... आनन्द जी, आपका नाम तो आनन्द है, आपको तो आनन्द होना चाहिए। सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, नरेंद्र मोदी जी अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने स्टार्ट-अप इंडिया के माध्यम से कम से कम 490 करोड़ रुपये हमारे लिए दे दिए हैं, कम से कम 52 हजार करोड़ रुपये ...(**व्यवधान**)...

एक माननीय सदस्यः यह हो रहा है। ...(**व्यवधान**)...

श्री रामदास अठावलेः बीच-बीच में कौन बोल रहे हैं? वहां कौन हैं?

श्री आनन्द शर्माः वे एम.पी. हैं, उनका नाम पूछिए।

श्री रामदास अठावलेः बोल लीजिए, लेकिन अभी जो सरकार चाहती है, उसमें एकदम से बदलाव होता नहीं है। ...(**व्यवधान**)... आपने काम इतना बिगाड़ दिया है ...(**व्यवधान**)... अगर देश को बदलना है तो उसके लिए चिंता मत कीजिए। ...(**व्यवधान**)... दलितों का आरक्षण कोई हटाने वाला नहीं है। ...(**व्यवधान**)... किसी ने कुछ भी बोला होगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने बताया है कि दलित, आदिवासियों, ओ.बी.सी. का आरक्षण बिल्कुल नहीं हटेगा। ...(**व्यवधान**)... सर, मेरा तो बहुत बार यह कहना है कि सभी जातियों को आरक्षण में हिस्सा मिलना चाहिए। दलित, आदिवासियों और ओबीसी के बाद जो ब्राह्मण समाज है, मराठा समाज है, पटेल समाज है, जाट समाज है, राजपूत समाज है, एस.सी./एस.टी., ओबीसी में...। इनमें जो समाज नहीं आता है, उस समाज को भी 50 परसेंट में से 25 परसेंट आरक्षण देने का कानून पार्लियामेंट को बनाना चाहिए, क्योंकि दूसरे समाजों में भी गरीबों की संख्या है। हमारे आरक्षण को धक्का मत लगाइए। हमारे आरक्षण को अगर धक्का लगाएंगे, तो हम सबको धक्का दे देंगे। ...(**व्यवधान**)... हमारे आरक्षण को धक्का मत दीजिए।

श्री आनन्द शर्माः किसने धक्का लगाने की बात कही है? ...(**व्यवधान**)...

श्री रामदास अठावलेः डिप्टी चेयरमैन सर, लेकिन आज हर समाज की तरफ से ऐसी मांग हो रही है, क्योंकि हर समाज में इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास की अपनी संख्या है। ...(**व्यवधान**)... तो उनके लिए आर्थिक बात लगाकर, आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते हैं ...(**व्यवधान**)...

श्री प्रफुल्ल पटेल (महाराष्ट्र): आप बिल लाओ।

श्री रामदास अठावले: आप बोलिए, तो बिल लाएंगे। उसमें आप सबका समर्थन आवश्यक है, टू थर्ड मेजोरिटी की आवश्यकता है। प्रफुल्ल जी, अभी आरक्षण देने के लिए महाराष्ट्र में इतने मराठा लोग आंदोलन कर रहे हैं। इतने साल गुजर गए, आप लोग बिल क्यों नहीं लाए? आपने बिल लाया नहीं।

श्री प्रफुल्ल पटेल: आप आरक्षण दो, अभी बिल लाओ।

श्री रामदास अठावले: आपने बिल नहीं लाया। ठीक है, प्रफुल्ल जी, बोल रहे हैं, यह कानून बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है। डिप्टी चेयरमैन सर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 50 परसेंट से आगे आरक्षण नहीं देना चाहिए, लेकिन मेरा मत है कि यह सुप्रीम कोर्ट की अपनी ओपिनियन है, पार्लियामेंट कानून तो बना सकती है। जाति के आधार पर आरक्षण मिलना ठीक है, लेकिन दो समाज का झगड़ा निपटाने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि दूसरे समाज कहते हैं कि इनको आरक्षण मिलता है, हमें नहीं मिलता है। इससे दो समाज में हमेशा झगड़ा पैदा हो रहा है। उनके मन में भावना उठती है कि हमें नहीं मिलता है। इसलिए तुम भी ले लो, जितना मिलता है, उतना ले लो, बाकी हम लेते हैं। ...(**व्यवधान**)... यह एक मुद्दा है और इसलिए मैं बार-बार यह बोल रहा हूँ कि कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट होना चाहिए। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने वक्त-वक्त पर कानून में बदल करने का अधिकार पार्लियामेंट को दे दिया है। अगर ऐसा कानून पास हो जाता है, तो सबको 25 परसेंट आरक्षण मिलेगा और इस प्रकार 75 परसेंट आरक्षण होगा। ...(**समय की घंटी**)... इसलिए इस आरक्षण के मुद्दे पर पर भी पार्लियामेंट को विचार करना चाहिए। इसमें आपको विचार करना चाहिए, इनको विचार करना चाहिए, उनको विचार करना चाहिए। एक मत से यह रिज़ॉल्यूशन पास हो सकता है। इसलिए यह विषय आपके सामने है। बाबा साहेब जी अम्बेडकर के संविधान को कोई बदल नहीं सकता है। आप लोग, आनन्द शर्मा जी और कांग्रेस वाले हमेशा बोलते हैं कि यह नरेंद्र मोदी जी की सरकार संविधान बदलेगी। संविधान कोई कैसे बदल सकता है? संविधान को जो बदलेगा, उसे पब्लिक बदल देगी। संविधान कोई नहीं बदल सकता है। आप लोग जो बदलने की कोशिश कर रहे थे, तो हमने आपको बदल दिया। ...(**व्यवधान**)... मेरा कहना यह है कि इसे बदलने की आवश्यकता नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

SHRI BHUBANESWAR KALITA: Sir, I am on a point of order. ...(*Interruptions*)... Sir, you have called the hon. Minister to speak now, although he was not present when his name was called earlier. ...(*Interruptions*)... You have given him a chance. ...(*Interruptions*)...

श्री प्रफुल्ल पटेल: जब तक आप एनसीपी के साथ थे, तब तक बराबर था।

श्री रामदास अठावले: हां, बराबर था। कुछ दिन तक कांग्रेस के साथ भी बराबर था, लेकिन बाद में फिर बिगड़ गया। ...(**व्यवधान**)...

SHRI BHUBANESWAR KALITA: Sir, he is making some statements as Minister. But, it appears to be irresponsible. He has pointed out some figures and made some statements which have not been authorized and are not true. He is talking about

6.00 P.M.

reservation. He is taking about Constitutional amendment. ...(*Interruptions*)... He is saying them so lightly which is a very serious thing. ...(*Interruptions*)...

SHRI RAMDAS ATHAWALE: No, no; not lightly. ...(*Interruptions*)...

SHRI BHUBANESWAR KALITA: I think, as Minister, he should know his rights and responsibilities and he should also know what to talk and what not to talk. ...(*Interruptions*)... What he is talking is irresponsible. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is his view. ...(*Interruptions*)...

श्री रामदास अठावलेः डिप्टी चेयरमैन सर, मेरी पार्टी का एक रिज़ॉल्यूशन हमने पास किया है। जब हमने समाज में देखा कि महाराष्ट्र में दस लाख, बीस लाख मराठा इकट्ठा होकर आ रहे हैं, हरियाणा में जाट इकट्ठा होकर आ रहे हैं, गुजरात में पटेल इकट्ठा होकर आ रहे हैं, तो हमने प्रस्तावित किया है। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, you conclude. ...(*Interruptions*)... Instead of five minutes, you have taken nine minutes. ...(*Interruptions*)... आपने पांच मिनट की जगह नौ मिनट लिए हैं। अब आप समाप्त करो। ...(**व्यवधान**)... अब आप समाप्त करो।

श्री रामदास अठावलेः सर, थोड़ा समय चाहिए।

श्री उपसभापतिः छह बजने वाले हैं। ....(**व्यवधान**)... हमें जाना है। ...(**व्यवधान**)...

श्री रामदास अठावलेः सर, मैंने बताया कि आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते ...(**व्यवधान**)... आरक्षण देने का बिल लाने में अभी मजबूरी है। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः आप बैठिए, बैठिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री रामदास अठावलेः सर, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री उपसभापतिः आप बैठिए, बैठिए। ...(**व्यवधान**).... मंत्री साहब बैठिए।

श्री रामदास अठावलेः मेरा इतना ही कहना है कि आप भी समर्थन करिए। नरेंद्र मोदी जी अच्छा काम कर रहे है, इसलिए मेरा समर्थन इनके साथ है। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, I have an announcement to make.

RECOMMENDATIONS OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have to inform Members that the Business Advisory Committee in its meeting held on the 7th of February, 2017, has allotted time for Government Legislative and other Business, as follows:–